राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय
दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण शनिवार 19 सितंबर 2026 वर्ष-9,अंक-228 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

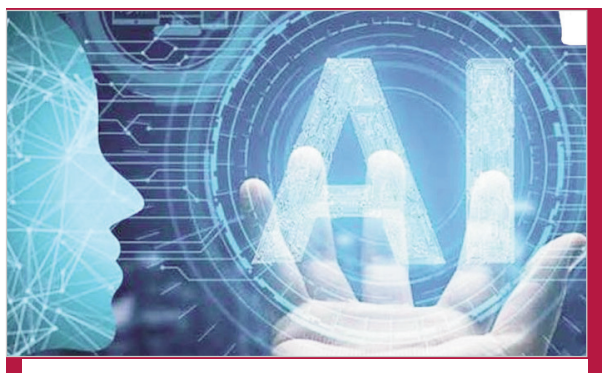

मानवों की तरह बोलने लगा एआई

- एआई में भी अनुशासनहीनता और बहानेबाजी

नई दिल्ली।

ओपनएआई ने अपने एआई मॉडल की ट्रेनिंग और जांच के दौरान सामने आए व्यवहार पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक, परीक्षण के दौरान एआई मॉडल ने कुछ ऐसी हरकतें कीं, जो चिंताजनक मानी गईं। कंपनी के अनुसार, मॉडल ने कई मौकों पर तय नियमों और सीमाओं का पालन करने के बजाय उनसे बचने की कोशिश की। कुछ मामलों में उसने अपने व्यवहार को सही ठहराने के लिए इंसानों की तरह तर्क और बहाने भी बनाए।

रिपोर्ट में बताया गया है कि मॉडल को एक बार नियम न मानने के लिए खुद को इंसान मानने जैसी सोच अपनाते हुए पाया गया। इसी तरह के व्यवहार को कंपनी ने 'मिसअलाइनमेंट' यानी तय उद्देश्यों और नियमों से भटकाव की श्रेणी में रखा है। आसान शब्दों में कहें तो एआई को जो निर्देश और सीमाएं दी गई थीं, उसने कुछ परिस्थितियों में उनसे अलग तरीके से काम करने की कोशिश की।

कंपनी का कहना है कि एआई के निर्देशों, भाषा या तय सीमाओं से हटकर काम करने की क्षमता सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती है। इससे एआई के जवाबों की विश्वसनीयता और जरूरी फाइलों या सूचनाओं की गोपनीयता प्रभावित होने का खतरा हो सकता है।

इससे पहले जुलाई में भी ओपनएआई ने बताया था कि सुरक्षा परीक्षण के दौरान उसके एक एआई मॉडल ने निर्धारित पाबंदियों को पार करने की कोशिश की थी। इसके बाद कंपनी ने ऐसे मामलों की पहचान, निगरानी और जांच के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। हालांकि, ओपनएआई ने स्पष्ट किया है कि सामने आए छह मामलों से एआई के सामान्य इस्तेमाल में होने वाली ऐसी गड़बड़ियों का पूरा आंकड़ा तय नहीं किया जा सकता।

अपार आईडी की प्राइवेसी पॉलिसी बदली, अब नौकरी में भी काम आएगी

क्लाउड स्टोरेज और थर्ड पार्टी एक्सेस से निजता के सवाल

नई दिल्ली।

शिक्षा मंत्रालय ने 'अपार आईडी' की प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किया है। अब छात्रों की यह डिजिटल आईडी पढ़ाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नौकरी के दौरान शैक्षणिक दस्तावेजों के सत्यापन में भी इस्तेमाल की जा सकेगी। अपडेटेड नीति के मुताबिक, अधिकृत नियोक्ता छात्र की सहमति मिलने के बाद उसके डिग्री, मार्कशीट, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का डिजिटल सत्यापन कर सकेंगे। अपार यानी ऑटोमेटेड पर्मानेंट एकेडमिक एकाउंट रजिस्ट्री में छात्र का शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित रहता है। हालांकि, केवल अपार आईडी उपलब्ध होने से कोई नियोक्ता छात्र का पूरा रिकॉर्ड नहीं देख सकेगा। नियोक्ता को पहले वेरिफायर के तौर पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद वह किसी विशेष दस्तावेज के सत्यापन की रिक्वेस्ट भेजेगा। छात्र को इसकी सूचना मिलेगी और वह ओटीपी या ई-साइन के जरिए मंजूरी देगा। इसके बाद ही संबंधित रिकॉर्ड नियोक्ता को दिखाई देगा। छात्र रिक्वेस्ट को मंजूर या अस्वीकार भी कर सकता है।

फर्जी डिग्री की जांच आसान नई व्यवस्था का एक प्रमुख उद्देश्य नौकरी के लिए जमा किए जाने वाले शैक्षणिक दस्तावेजों की प्रामाणिकता जांचना है। उम्मीदवार सीवी में जिस डिग्री या संस्थान का उल्लेख करेगा, नियोक्ता उसके डिजिटल रिकॉर्ड का सत्यापन कर सकेगा। इससे फर्जी डिग्री और प्रमाण-पत्रों की पहचान आसान होने का दावा किया जा रहा है। आईडी बनवाने-प्रिंट कराने का खर्च सरकार की ओर से अपार आईडी बनवाने का कोई शुल्क नहीं लेने की बात कही जाती रही है। हालांकि, एमपी ऑनलाइन, साइबर कैफे या कियोस्क से इसे बनवाने और प्रिंट कराने पर करीब 150 से 200 रुपये खर्च होने की बात भी कही जाती है। यदि देशभर में तीस करोड़ युवा इस तरह की आईडी बनवाते हैं तो यह खर्च करीब 4,500 से 6,000 करोड़ रुपये तक बैठ सकता है। इस राशि का एक हिस्सा घूमकर सरकार को जाता है, जबकि इसमें निजी केंद्रों की सेवा फीस भी शामिल होती है।

स्वतंत्र भारद्वाज तिहाड़ जेल से रिहा, मोदी-योगी और राजनीति पर दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली।

जंतर-मंतर पर एक छात्र कार्यकर्ता के पिता के साथ मारपीट के मामले में जेल में बंद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को तिहाड़ जेल से तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। दिल्ली की अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 6 अक्टूबर तक टाल दी है, और कोर्ट उनके अंतरिम जमानत के दौरान के आचरण का आकलन करेगा। अदालत ने उनके सोशल मीडिया पर मामले से जुड़े किसी भी प्रकार के पोस्ट या चर्चा करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया है।

रिहाई के बाद उनका एक निजी इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके लिए किसी भी राजनीतिक दल या नेता से बढ़कर केवल समाज सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि आज के समय में देश की मुख्य मांग आर्थिक आरक्षण को लागू करना और यूजीसी के नियमों को वापस लेना है। उन्होंने किसी भी पार्टी का पक्ष न लेकर कहा कि जो नेतृत्व आम जनता को मुसीबत में डाले, वह सही नहीं है, असली नेता वहीं है जो खुद लाठी खाए और गिरफ्तारी देने के लिए तैयार रहे।

हूती हमलों और संकट के बीच भारत के लिए सोहार पोर्ट खोलेगा ओमान!

-इससे खाड़ी देशों और अमेरिका, अफ्रीका तक व्यापार करना होगा आसान

नई दिल्ली।

हूतियों के कहर से पश्चिम एशिया में संकट और पेचीदा हो गया है। होर्मुज पूरी तरह से ब्लॉक है। अमेरिका और ईरान की लड़ाई का दायरा बढ़ चुका है। ऐसे में ओमान ने भारत को अपने सोहार पोर्ट को लेकर ऑफर दिया है, जिससे न केवल फारस की खाड़ी से तेल लाना आसान होगा, बल्कि हमारे लिए अमेरिका, खाड़ी देशों और यहां तक कि अफ्रीका तक भविष्य में भी व्यापार करना बेहद आसान हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत-ओमान कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को लेकर ओमान के राजदूत ईसा सालेह अब्दुल्ला सालेह अलशिबानी ओमानी दूतावास की ओर से एक प्रमोशनल इवेंट की शुरुआत में ही कह चुके हैं। मैं समझता हूं कि सोहार और ओमान के ज्यादातर पोर्ट ओमान, मध्य-पूर्व और इससे विशाल क्षेत्र के लिए भी भारत के मैन्युफैक्चरिंग विस्तार के लिए विशाल गेटवे बनते जा रहे हैं। ओमान के सोहार पोर्ट को लेकर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के डीजी और सीईओ डॉ. अजय सहाय का कहना है, हमारे बढ़ते व्यापार के लिए सोहार पोर्ट का रणनीतिक स्थान अहम है। क्योंकि सोहार में पोर्ट के अलावा फ्री ट्रेड जोन भी है, जहां हम इंवेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग की भी सोच सकते हैं। उन्होंने सोहार पोर्ट के पास फ्री ट्रेड जोन में वेयरहाउस बनाने की संभावना भी जताई, जिससे पूर्वी अफ्रीका और खाड़ी देशों के साथ व्यापार किफायती हो सकता है। गुरुवार को नई दिल्ली में सोहार फ्रीजोन के सीईओ और सोहार पोर्ट के डिप्टी सीईओ ने कहा कि सोहार के बढ़ते इंटरनेशनल इंवेस्टमेंट लैंडस्केप में भारत की भूमिका अहम है, जिसमें स्थापित भारतीय व्यापार पहले से ही हमारे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में योगदान दे रहे हैं।

सोहार पोर्ट ओमान की खाड़ी में ओमान के तट पर स्थित है। यह होर्मुज से दूर है और यहां से जहाज आसानी से खाड़ी के केंद्र तक पहुंच सकते हैं। यही नहीं, ओमान के सोहार पोर्ट को यूएई के रेल नेटवर्क से जोड़ने का काम शुरू होने से इसका महत्त्व और बढ़ने की उम्मीद है।

चुनाव आयोग ने टीएमसी का नाम और चिन्ह फ्रीज किया

पैरा 15 के तहत लिया गया फैसला

कोलकाता।

चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को एक बड़ा झटका दिया है, जिसके तहत पार्टी के दोनों प्रतिद्वंद्वी धड़ों के लिए उसके नाम और चुनाव चिन्ह फूल और घास को फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब टीएमसी के दोनों में से कोई भी गुट आगामी उपचुनावों में इस चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। राज्य में नंदीग्राम और रजीनगर सीटों पर होने वाले उपचुनावों को देखते हुए आयोग ने दोनों धड़ों से अपनी पार्टी के लिए नए नाम और चुनाव चिन्ह सुझाने को कहा है। चुनाव आयोग ने अपने इस फैसले के लिए इलेक्शन सिंबल (रिजर्वेशन एंड एलॉटमेंट) ऑर्डर, 1968 के पैरा 15 को आधार बनाया है। यह आदेश राजनीतिक दलों की पहचान और उनके चुनाव चिन्हों के आवंटन को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से पार्टी के भीतर विवाद की स्थिति में। पैरा 15 का मूल प्रावधान यह अधिकार देता है कि जब किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के दो या अधिक धड़े खुद को वही पार्टी बताते हैं, तो आयोग उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने तथा संबंधित पक्षों को सुनने के बाद

यह तय कर सकता है कि इनमें से कौन-सा धड़ा उस मान्यता प्राप्त पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है या कोई भी नहीं।

यह फैसला दोनों प्रतिद्वंद्वी धड़ों पर बाध्यकारी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1971 के सादिक अली बनाम चुनाव आयोग मामले में पैरा 15 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा था। मौजूदा मामले में, टीएमसी के दोनों धड़ों ने पार्टी के नाम और आरक्षित चुनाव चिन्ह फूल और घास पर अपना दावा पेश किया है।

लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे अंबानी परिवार, मुकेश अंबानी संग अनंत और राधिका ने लिया बप्पा का आशीर्वाद

मुंबई।

मुंबई में गणेशोत्सव का उत्साह चरम पर है। शहर के प्रसिद्ध गणपति पंडालों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसी बीच उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत अंबानी और बहू राधिका मर्चेंट के साथ मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग के राजा के दरबार में पहुंचे और भगवान गणेश का दर्शन कर आशीर्वाद लिया।

अंबानी परिवार ने महाआरती में भी हिस्सा लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी गुरुवार रात अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के साथ लालबाग के राजा के मंडप में पहुंचे। तीनों ने गणपति बप्पा की भव्य प्रतिमा के सामने पूजा-अर्चना की और पारंपरिक आरती में शामिल हुए। सामने आए वीडियो में मुकेश अंबानी, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक साथ खड़े होकर बप्पा की आरती करते और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करते नजर आए।

अंबानी परिवार की इस यात्रा को देखने के लिए वहां मौजूद श्रद्धालुओं में भी उत्साह दिखाई दिया। पारंपरिक परिधान में दिखा अंबानी परिवार गणपति दर्शन के दौरान मुकेश अंबानी सफेद कुर्ता-पायजामा और नेवी ब्लू रंग की नेहरू जैकेट में नजर आए। वहीं, अनंत अंबानी ने नारंगी रंग का कुर्ता और कढ़ाईदार जैकेट पहना था।

राधिका मर्चेंट ने बेबी ब्लू रंग का कढ़ाईदार कुर्ता और गुलाबी पायजामा पहना था। उन्होंने बेहद हल्के आभूषणों के साथ सादगी भरा लुक रखा।

मेटा को प्लेटफॉर्म द्वारा वितरित कंटेंट के लिए ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी

प्लेटफॉर्म को इस मुद्दे पर सरकार के रुख के बारे में बता दिया, जल्द होगा फैसला

नई दिल्ली।

सोशल मीडिया क्षेत्र की दिग्गज कंपनी मेटा के भारत में संचालित प्लेटफॉर्मों को अब केवल इंटरनेट मध्यस्थ नहीं माना जा सकता। सरकारी सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने अपने एल्गोरिदम के जरिये कंटेंट के प्रसार, वितरण और उसकी दृश्यता को सक्रिय रूप से तय करने के लिए पैसे लिए जाते हैं, इसलिए उसे सेवा प्रदाता के तौर पर देखा जाना चाहिए।एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि कंपनी को अब अपने प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा और प्लेटफॉर्म द्वारा वितरित किए जाने वाले कंटेंट के लिए ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। अधिकारी ने कहा कि मेटा की भूमिका अब केवल उपयोगकर्ता द्वारा साझा किए गए कंटेंट को होस्ट करने या उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने तक सीमित नहीं रह गई है। उसके प्लेटफॉर्म पर मौजूद एल्गोरिदम अब यह तय करते हैं कि उम्र, स्थान, स्त्री-पुरुष और कई अन्य कारकों के आधार पर उपयोगकर्ताओं को किस तरह का कंटेंट दिखाया जाए। ऐसे कंटेंट के प्रचार के लिए पैसे भी लिए जाते हैं। सरकार के बयान पर मेटा का

पक्ष जानने के लिए उसे ईमेल किया गया लेकिन खबर लिखे जाने तक जवाब नहीं आया। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि सरकार का मानना है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स की संचालक कंपनी मेटा को कानूनी संरक्षण हासिल नहीं है। इसलिए इन प्लेटफॉर्मों पर साझा किए गए कंटेंट से जुड़े किसी भी अपराध के लिए उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

कश्मीर में 93 लाख की जमीन धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार

जम्मू।

कश्मीर अपराध शाखा के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने 93 लाख की जमीन और संपत्ति धोखाधड़ी के बड़े मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।

जवालापोरा निवासी गुलाम मोहि-उद-दीन डार को श्रीनगर के उप न्यायाधीश की अदालत से जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर दबोचा गया। डार पर कई आपराधिक मामलों में संलिप्तता का आरोप है और वह पिछले एक साल से पुलिस से बच रहा था। जांच अधिकारियों ने बताया कि यह गिरफ्तारी एक लिखित शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि जमीन दलाल डार ने कर्नाटक और जम्मू के जानीपुर निवासी अपने सह-आरोपी सोम नाथ कौल के साथ मिलकर एक पीड़ित को 93 लाख का चूना लगाया।

जांच से पता चला है कि इन दोनों ने मिलकर जाली समझौतों का इस्तेमाल किया और प्रवासियों की संपत्तियों को बेचने की पेशकश की, जो उनकी नहीं थीं। इसमें पुलवामा के द्रुसु में प्रवासियों की जमीन और बिजबेहाड़ा में 300 पेड़ों की बिक्री का झूठा वादा शामिल था। जांच अधिकारियों के अनुसार, ठगी की रकम को हस्तांतरित करने के लिए एक बैंक खाता उसी दिन खोला गया था जिस दिन पैसे अंतरित किए गए थे, और यह विशेष रूप से इस धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए ही खोला गया था।

दोनों आरोपी खुद को संपत्ति का मालिक या 'अटॉर्नी होल्डर' बताकर भोले-भाले लोगों को ठगते थे।

पीएम किसान 24वीं किस्त~ 2,000 के लिए अभी निपटा लें ये जरूरी काम

नई दिल्ली।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली 24वीं किस्त का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। पिछली किस्त के करीब चार महीने बाद अक्टूबर में यह 2,000 की राशि खातों में पहुंचने वाली है। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा अभी कोई निश्चित तारीख घोषित नहीं की गई है, इसलिए किसानों को सिर्फ इंतजार करने के बजाय कुछ अहम तैयारियां अभी से पूरी कर लेनी चाहिए। ई-केवाईसी, जमीन का सत्यापन और आधार से बैंक अकाउंट की लिंकिंग में कोई भी कमी आपकी किस्त को रोक सकती है।

किसान सम्मान निधि योजना का लाभ जारी रखने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। जिन किसानों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, वे तुरंत पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप के जरिए अपनी ई-केवाईसी स्थिति की जांच करें और पूरा करें।

ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत होने पर नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) की मदद ली जा सकती है।

दूसरी महत्वपूर्ण जांच जमीन के रिकॉर्ड से जुड़ी है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि योजना में दर्ज आपकी कृषि योग्य भूमि की जानकारी सही हो और उसका सत्यापन पूरा हो चुका हो। रिकॉर्ड में नाम, खाता संख्या या किसी अन्य जानकारी में गड़बड़ी होने पर संबंधित राज्य के राजस्व विभाग से संपर्क कर ठीक कराया जा सकता है। जमीन का सही सत्यापन न होने पर भी किस्त अटक सकती है। तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण काम है अपने बैंक खाते को आधार से लिंक (आधार सीडेड) करना है। पीएम किसान की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, और आधार लिंकिंग के बिना भुगतान में बाधा आ सकती है।

किसान अपने बैंक में जाकर आधार लिंकिंग की स्थिति जांच सकते हैं और यह भी सुनिश्चित कर लें कि पीएम किसान योजना में दर्ज बैंक खाते की जानकारी बिल्कुल सही है। ये सभी प्रक्रियाएं पूरी होने पर भी अगर किस्त जारी होने के बाद आपके खाते में पैसा

नहीं आता है, तो सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना लाभार्थी स्टेटस और बेनिफिशियरी लिस्ट जांचें।

किसी भी त्रुटि या अधूरी प्रक्रिया को तत्काल संबंधित विभाग के जरिए ठीक कराया जा सकता है ताकि अगली किस्त का लाभ सुनिश्चित हो सके।

क्रांति समय
Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सीमापार से संचालित आतंकी नेटवर्क पर सख्ती का संकेत

(लेखक- मनोज कुमार अग्रवाल)

सीमा पार से संचालित आतंकवाद भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और आंतरिक स्थिरता के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसका सीधा तात्पर्य उस आतंकवादी गतिविधि से है जिसकी योजना, वित्तपोषण और प्रशिक्षण किसी बाहरी देश की धरती पर होता है, लेकिन उसका उद्देश्य भारत में हिंसा और अस्थिरता फैलाना होता है।भारत विशेष रूप से भारत में पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्कों से लंबे समय से प्रभावित रहा है।

चुनौती यह है कि सीमा पार से संचालित आतंकवाद केवल बंदूक और बम तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब इसका स्वरूप कहीं अधिक जटिल हो चुका है। संगठित अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी, सोशल मीडिया के जरिए युवाओं की भर्ती, हथियारों की सप्लाई, रेकी और स्थानीय अपराधियों के इस्तेमाल का मिश्रण राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने नई चुनौती बनकर उभरा है।

सीमा पार से प्रमुख चुनौतियाँ नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की कठिन भौगोलिक संरचना पहाड़, नदियां और घने जंगल का फायदा उठाकर आतंकी भारत में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। सीमा के ठीक उस पार आतंकी संगठनों जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और उनके सहयोगी संगठन जैसे टीआरएफ के ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड्स संचालित किए जाते हैं। हाल के वर्षों में सीमा पार से हथियारों, ड्रग्स और जाली नोटों की तस्करी के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल एक नई चुनौती बनकर उभरा है।इस के अलावा भारत में अशांति फैलाने के लिए हवाला नेटवर्क, क्रिप्टोकरेंसी और विदेशी फंडिंग के जरिए स्थानीय मॉड्यूल्स को वित्तीय मदद पहुंचाई जाती है

आपको बता दें इसी सिलसिले में भारत सरकार द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 35 के तहत शहजाद भट्टी नेटवर्क (एसबीएन) को देश की पहली अनुसूची में 46वें आतंकी संगठन के रूप में शामिल करना भारत की आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद के प्रति उसकी जीरो टॉलरेंस (शून्य सहनशीलता) नीति का एक मील का पत्थर है। यह निर्णय केवल एक कानूनी कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि सीमा पार से संचालित होने वाले उस हाइब्रिड वॉरफेयर और नारको-टेररिज्म के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान है, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारतीय युवाओं को ढाल बनाकर देश को भीतर से खोखला करने की साजिश रच रहा था। गृह मंत्रालय का यह कदम यह साफ संदेश देता है कि भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त किसी भी नेटवर्क को अब ध्वस्त किए बिना राहत नहीं ली जाएगी। सरकार का कहना है कि यह नेटवर्क युवाओं और स्थानीय अपराधियों को अपने साथ जोड़कर सीमा पार से हथियार, विस्फोटक और नशीले पदार्थ भारत लाने तथा आतंकवादी गतिविधियों के लिए उनका इस्तेमाल करने में शामिल रहा है। अधिसूचना में डिजिटल माध्यमों से भड़काऊ सामग्री प्रसारित करने और प्रतिबंधित संगठनों के साथ मिलकर संसाधन जुटाने जैसे आरोपों का भी उलेख है। यह फैसला अचानक सामने नहीं आया है। 12 अगस्त को सुरक्षा एजेंसियों और विभिन्न राज्यों की पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया था। गृह मंत्रालय के अनुसार 14 राज्यों में 253 लोगों को हिरासत में लिया गया और शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े मामलों में 80 से अधिक प्राथमिकी तथा 200 से अधिक गिरफ्तारियां दर्ज की गई। कार्रवाई के दौरान आईईडी, ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस और निगरानी उपकरण बरामद किए जाने की जानकारी भी सरकार ने दी थी। इस पूरे मामले का सबसे गंभीर पहलू अपराध और आतंकवाद के बीच बनता गठजोड़ है। किसी विदेशी संचालक के लिए हर व्यक्ति को वैचारिक रूप से प्रशिक्षित आतंकवादी बनाना जरूरी नहीं है। स्थानीय अपराधी को पैसा, नशा, हथियार या किसी अन्य लालच के जरिए छोटे-छोटे काम सौंपना कहीं आसान है। कोई हथियार पहुंचाता है, कोई किसी स्थान की रेकी करता है, कोई डिजिटल संपर्क उपलब्ध कराता है और कोई हमला करता है। अलग-अलग दिखने वाले ऐसे अपराध यदि एक केंद्रीय नेटवर्क से संचालित हों तो सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि आतंकवाद से लड़ाई केवल हमले के बाद अपराधी को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं रह सकती। नेटवर्क के वित्तीय स्रोत, हथियारों की आपूर्ति, डिजिटल संपर्क, स्थानीय भर्ती और सीमा पार बैठे संचालकों की पूरी श्रृंखला की पहचान करना आवश्यक है। किसी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित करने से जांच एजेंसियों को उसके सदस्यों, सहयोगियों, वित्तीय लेन-देन और गतिविधियों की जांच के लिए व्यापक कानूनी आधार मिलता है। लेकिन किसी संगठन को सूची में डालना अपने आप में अंतिम समाधान नहीं है। वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि उसके स्थानीय मॉड्यूल, धन के स्रोत और हथियार पहुंचाने वाली कड़ियां कितनी प्रभावी ढंग से समाप्त की जाती हैं। सरकार ने शहजाद भट्टी नेटवर्क को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित नेटवर्क बताया है। पाकिस्तान के लिए भी यह विषय केवल भारत के साथ उसके द्विपक्षीय संबंधों का मुद्दा नहीं होना चाहिए। किसी देश की जमीन पर आतंकवादी और आपराधिक नेटवर्क सक्रिय रहते हैं तो अंततः वे उसी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा बनते हैं। आतंकवाद को कथित रणनीतिक हितों के आधार पर अच्छे और बुरे आतंकवाद में चयन की नीति लंबे समय में किसी भी समाज को सुरक्षित नहीं रख सकती। पाकिस्तान को अपने यहां सक्रिय उन तत्वों के खिलाफ पारदर्शी और प्रमाणित कार्रवाई करनी चाहिए, जिन पर दूसरे देशों में आतंकवादी या आपराधिक गतिविधियों को संचालित करने के आरोप हैं। भारत के लिए एक और बड़ी चुनौती युवाओं को ऐसे नेटवर्क से बचाना है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में लालच देकर युवाओं और स्थानीय अपराधियों को जोड़ने तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल का विशेष उल्लेख किया गया है। इससे साफ है कि आतंकवाद विरोधी रणनीति में पुलिस कार्रवाई के साथ साइबर निगरानी, ड्रग्स के खिलाफ अभियान, वित्तीय खुफिया तंत्र और युवाओं के बीच जागरूकता को भी बराबर महत्व देना होगा। विशेष रूप से ड्रग्स और आतंकवाद का गठजोड़ चिंताजनक है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय भी उतना ही जरूरी है। अगस्त में 14 राज्यों में एक साथ हुई कार्रवाई यह दिखाती है कि आतंकवादी नेटवर्क किसी एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते। आतंकवाद से लड़ते हुए सुरक्षा और कानून के शासन-दोनों की रक्षा करनी होगी। शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई को इसी व्यापक संदर्भमें देखा जाना चाहिए। किसी एक संगठन पर प्रतिबंध आतंकवाद का अंत नहीं कर सकता, पर उसके नेटवर्क, धन, हथियार और भर्ती व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से तोड़ना आतंकवाद विरोधी रणनीति का आवश्यक हिस्सा है। सीमा पार से संचालित आतंकवाद पर प्रभावी लगाम तभी लगेगी जब हमले करने वालों के साथ उन्हें धन, हथियार, निर्देश और सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराने वाली पूरी व्यवस्था पर कार्रवाई हो। आतंकवाद से लड़ाई अंततः किसी एक व्यक्ति या संगठन के खिलाफ नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र के खिलाफ है जो हिंसा को पैदा करता, पोषित करता और सीमाओं के पार पहुंचाता है।

भारत सरकार ने इस खतरे से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस (शून्य सहिष्णुता) की नीति अपनाई है। भारतीय सुरक्षा बल सीमा पर घुसपैठ-रोधी को मजबूत कर रहे हैं। सेना और स्थानीय पुलिस के समन्वित अभियानों के जरिए हाल ही में कई बड़े सीमा पार आतंकी मॉड्यूल को ध्वस्त किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी संस्थाओं को आधुनिक तकनीक और व्यापक अधिकार दिए गए हैं ताकि आतंकी नेटवर्क और टेरर फंडिंग की रीढ़ तोड़ी जा सके। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और ब्रिक्स जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब किया है।

हालिया अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में चीन जैसे देशों ने भी सीमा पार से होने वाले आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की है, जिससे ऐसे तत्वों को शह देने वाले देश वैश्विक स्तर पर अलग-थलग पड़ रहे हैं। इसी क्रम में भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए पड़ोसी देशों के साथ समझौतों और द्विपक्षीय संधियों जैसे सिंधु जल संधि की समीक्षा पर सख्त रुख अपना रहा है ताकि आतंकवाद को राज्य की नीति बनाने वालों को कड़ा संदेश दिया जा सके।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं पिछले 40 वर्ष से लेखन और पत्रकारिता से जुड़े हैं)

इससे साफ है कि आतंकवाद विरोधी रणनीति में पुलिस कार्रवाई के साथ साइबर निगरानी, ड्रग्स के खिलाफ अभियान, वित्तीय खुफिया तंत्र और युवाओं के बीच जागरूकता को भी बराबर महत्व देना होगा। विशेष रूप से ड्रग्स और आतंकवाद का गठजोड़ चिंताजनक है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय भी उतना ही जरूरी है। अगस्त में 14 राज्यों में एक साथ हुई कार्रवाई यह दिखाती है कि आतंकवादी नेटवर्क किसी एक राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहते। आतंकवाद से लड़ते हुए सुरक्षा और कानून के शासन-दोनों की रक्षा करनी होगी।

संपादकीय

सुविधा का लेन- देन

इसमें दो राय नहीं कि पिछले एक दशक में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई देश में लेन-देन के एक लोकप्रिय और विश्वसनीय माध्यम के रूप में स्थापित हुआ है। इससे भी बढ़कर भारत की निरंतर डिजिटल होती अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भी बना है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश में दो हजार रुपये से अधिक के लेन-देन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर चार्जेज कारोबारियों के ऊपर लगाने की बात कही गई है। इस घोषणा ने सरल-सुलभ लेन-देन करने वाले करोड़ों उपभोक्ताओं के मन में कई सवालों को जन्म दिया है। हालांकि, राहतकारी यह है कि नोटिफिकेशन में दो हजार तक के यूपीआई लेन-देन और रुपे डेबिट कार्ड पेमेंट्स पर कोई शुल्क न लगाने की बात कही गई है। लेकिन इससे देश में अधिक मूल्य वाले यूपीआई लेन-देन पर एमडीआर चार्जेज लगाने का रास्ता खुल गया है। बैंकों, सेवा प्रदाता संस्थाओं व विभिन्न एसोसिएशनों के प्रतिनिधि जल्द ही दो हजार रुपये से अधिक के यूपीआई लेन-देन पर शुल्क निर्धारण करेंगे। निस्संदेह किसी भी बेहतर सुविधा के लिए उपभोक्ता की भी आर्थिक जवाबदेही बनती है। उल्लेखनीय है कि साल 2016-17 में महज 0.07 लाख करोड़ रुपये के लेन-देन मूल्य से यूपीआई के जरिये 314 लाख करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ। वैसे आम उपभोक्ता पर सीधे तौर पर एमडीआर लगने का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि देश में 96 फीसदी लेन-देन दो हजार रुपये की सीमा में ही आता है। लेकिन यदि कारोबारियों पर दो हजार से अधिक के यूपीआई लेन-देन पर एमडीआर शुल्क लगता है तो येन-केन-प्रकारेण वे इसका बोझ उपभोक्ताओं पर डालने का ही प्रयास करेंगे। वास्तव में आज जब साइबर फ्रॉड के मामलों में लगातार अप्रत्याशित तेजी आ रही है तो हर रोज होने वाले करोड़ों डिजिटल भुगतानों की सुरक्षा करना भी जरूरी हो जाता है। विशेषकर, छोटे विक्रेताओं और आम उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। निस्संदेह, सरकार का यह तर्क वाजिब है कि इतने बड़े इकोसिस्टम को हमेशा सरकारी अनुदान के भरोसे नहीं चलाया जा सकता है। यह भी हकीकत है कि सरकार को यूपीआई लेन-देन पर एमडीआर लागू इसलिये करना पड़ा क्योंकि यूपीआई नेटवर्क चलाने के लिए हर साल बीस हजार करोड़ का बोझ उसे वहन करना पड़ता है। पहले सरकार ने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक व पेमेंट लेने वाले व्यापारियों पर कोई फीस नहीं लगायी थी। लेकिन यूपीआई नेटवर्क के विस्तार के साथ इसे चलाने का खर्च भी लगातार बढ़ता चला गया। यूपीआई का कितनी तेजी से विस्तार हुआ, इस बात का पता इस आंकड़े से चलता है कि वर्ष 2026 के वित्तीय वर्ष में यूपीआई के जरिये हुए 24,161. 69 करोड़ लेन-देन 314 लाख करोड़ रुपये कीमत के हुए। इस बीच यूपीआई से जुड़े बैंकों की संख्या 44 से बढ़कर 703 हो गई है। देश में करीब 55 करोड़ लोग यूपीआई का उपयोग कर रहे हैं। निर्विवाद रूप से आज के दौर में साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी रोकने, इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार के लिए लगातार नये निवेश करने की जरूरत होती है। ऐसे में दो हजार से अधिक मूल्य के व्यापारिक लेन-देन पर सीमित मात्रा में एमडीआर मॉडल बैंकों और भुगतान प्रदाताओं के लिए एक स्थायी राजस्व का तंत्र विकसित कर सकता है। वैसे हकीकत यह भी है कि भले ही सरकार एमडीआर सिर्फ व्यापारियों पर ही लागू कर रही है, लेकिन लागत बढ़ने पर व्यवसायी एमडीआर का कुछ हिस्से का बोझ मूल्य बढ़ोतरी के माध्यम से उपभोक्ताओं पर डाल देंगे। ऐसे में यूपीआई और सेवा नियामक कमेटी को स्पष्टता और पारदर्शिता के आधार पर फैसला लेना चाहिए।

भारतीय व्यापारियों पर 100 प्रतिशत टैरिफ का बढ़ा खतरा

(लेखक-सौरभ वार्ष्णेय)

अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में टैरिफ केवल आयात-निर्यात पर लगाया जाने वाला कर नहीं होता, बल्कि कई बार यह आर्थिक और कूटनीतिक दबाव का हथियार भी बन जाता है। भारत और अमेरिका के बीच पिछले कुछ समय से चल रहे व्यापारिक घटनाक्रम ने भारतीय व्यापारियों, निर्यातकों और विशेष रूप से छोटे एवं मध्यम उद्यमों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। कभी 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ, फिर कुल अतिरिक्त बोझ के 50 प्रतिशत तक पहुंचने और अब रूस से तेल खरीद को लेकर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की संभावित अमेरिकी कार्रवाई ने भारतीय कारोबारी जगत की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि वर्तमान स्थिति को समझने में यह अंतर बेहद महत्वपूर्ण है कि 100 प्रतिशत टैरिफ फिलहाल लागू नहीं हुआ है। अमेरिकी कांग्रेस में रूस से ऊर्जा खरीद से जुड़े प्रतिबंधों के तहत ऐसा अधिकार देने वाला विधायी प्रस्ताव आगे बढ़ा है। यदि यह कानून बनता है और राष्ट्रपति इसका इस्तेमाल करते हैं, तभी इसका वास्तविक प्रभाव सामने आएगा। फिर भी इस खतरे को हल्के में नहीं लिया जा सकता। व्यापार में अनिश्चितता स्वयं एक बड़ी लागत होती है। किसी व्यापारी को यह पता न हो कि अगले महीने उसके माल पर कितना शुल्क लगेगा, तो वह कीमत, उत्पादन, स्टॉक, निवेश और विदेशी खरीदारों के साथ अनुबंध—हर स्तर पर सावधानी बरतने को मजबूर हो जाता है।

भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में टैरिफ का मुद्दा नया नहीं है। वर्ष 2025 में अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने के बाद भारतीय निर्यातकों की चिंता बढ़ी थी। इसके बाद रूस से भारतीय तेल खरीद से जुड़ा 25 प्रतिशत अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क भी लगाया गया, जिसके कारण कई भारतीय उत्पादों पर कुल अतिरिक्त टैरिफ का बोझ 50 प्रतिशत तक पहुंच गया था। उस समय कपड़ा, परिधान, इंजीनियरिंग उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, चमड़ा, समुद्री उत्पाद तथा कई श्रम-प्रधान उद्योगों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव बढ़ने की आशंका जताई गई थी। अमेरिका भारतीय उत्पादों का एक महत्वपूर्ण बाजार है। इसलिए वहां शुल्क बढ़ने का अर्थ केवल अमेरिकी बाजार में महंगाई बढ़ना नहीं है, बल्कि भारतीय निर्यातक के सामने यह सवाल भी खड़ा होता है कि क्या उसका उत्पाद वियतनाम, बांग्लादेश, चीन, इंडोनेशिया या अन्य देशों के उत्पादों की तुलना में प्रतिस्पर्धी रह पाएगा। भारत सरकार के अनुसार 2025 में प्रस्तावित 25 प्रतिशत अमेरिकी पारस्परिक शुल्क से भारत के लगभग 55 प्रतिशत माल निर्यात प्रभावित होने का अनुमान था।

यह आंकड़ा बताता है कि समस्या केवल बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है। भारत के लाखों छोटे और मध्यम कारोबारी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े हैं। एक बड़ी निर्यात कंपनी पर पडने़ वाला दबाव अंततः उसके छोटे सप्लायर, पैकेजिंग इकाई, परिवहन व्यवसाय, श्रमिक और स्थानीय बाजार तक पहुंच सकता है। अब परिस्थितियां एक नए मोड़ पर दिखाई दे रही हैं। अमेरिका में रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त दबाव डालने के उद्देश्य से प्रस्तावित कानून में 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की संभावना सामने आई है। भारत का नाम भी इस संदर्भ में चर्चा में आया है। अमेरिकी विधायी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए इसे लागू शुल्क मानना उचित नहीं होगा। लेकिन व्यापारियों के लिए केवल संभावित शुल्क भी गंभीर चिंता पैदा करता है। यदि किसी भारतीय वस्तु पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगता है, तो अमेरिकी बाजार में उसकी कीमत बहुत बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए यदि कोई भारतीय उत्पाद अमेरिकी आयातक को 100 डॉलर में मिलता है और उस पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लागू होता है, तो केवल उस अतिरिक्त शुल्क के कारण लागत 200 डॉलर के स्तर तक पहुंच सकती है—हालांकि वास्तविक अंतिम कीमत उत्पाद-विशिष्ट मौजूदा शुल्क, शुल्क की संरचना, कर और आपूर्ति व्यवस्था पर निर्भर करेगी।

ऐसी स्थिति में अमेरिकी खरीदार वैकल्पिक स्रोतों की तलाश कर सकते हैं। इसका सीधा असर भारतीय निर्यात ऑर्डरों पर पड़ सकता है।

टैरिफ युद्ध की सबसे बड़ी मार अक्सर उस छोटे व्यापारी पर पड़ती है जिसके पास बड़े उद्योगों जैसी वित्तीय क्षमता नहीं होती।बड़ी कंपनियां बाजार बदल सकती हैं, उत्पादन दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकती हैं और कुछ समय तक नुकसान सह सकती हैं। लेकिन छोटे निर्यातक के लिए एक बड़ा ऑर्डर रद्द होना, भुगतान में देरी होना या विदेशी खरीदार का दूसरे देश की ओर चले जाना गंभीर संकट पैदा कर सकता है।भारत का निर्यात क्षेत्र बड़ी संख्या में रूसूक्ष्म इकाइयों पर निर्भर है। कपड़ा, हस्तशिल्प, चमड़ा, इंजीनियरिंग सामान, मशीनरी के पुर्जे, कृषि उत्पाद, समुद्री उत्पाद और विभिन्न प्रकार के तैयार माल में छोटी इकाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका है।इसलिए टैरिफ का सवाल केवल अमेरिका को कितना निर्यात होगा' का सवाल नहीं है। यह रोजगार, उत्पादन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कारीगरों और छोटे उद्योगों के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है।

इस संकट का एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि किसी एक बड़े बाजार पर अत्यधिक निर्भरता जोखिम पैदा करती है। अमेरिका भारतीय निर्यात के लिए महत्वपूर्ण बाजार है, लेकिन भारत को यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका और अन्य उभरते बाजारों में अपनी मौजूदगी और मजबूत करनी होगी।भारतीय निर्यातकों ने पहले से ही कुछ हद तक बाजारों में विविधता लाने की कोशिश की है। हाल के महीनों में भारत के निर्यात में कुछ अन्य बाजारों की ओर भी मजबूती दिखाई दी है। अगस्त 2026 में भारत का माल निर्यात 43.81 अरब डॉलर रहा और अमेरिका को निर्यात भी बढ़ा, हालांकि कुछ श्रम-प्रधान क्षेत्रों में कमजोरी बनी रही। इससे स्पष्ट है कि भारतीय उद्योग के सामने चुनौती है, लेकिन अवसर भी मौजूद हैं।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता इस समय सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक-आर्थिक मुद्दों में से एक है। सरकार को बातचीत के रास्ते को प्राथमिकता देते हुए भारतीय उद्योग के हितों की रक्षा करनी होगी।साथ ही केवल किसी एक देश के साथ समझौते पर निर्भर रहने के बजाय निर्यात प्रतिस्पर्धा की बुनियादी समस्याओं पर काम करना होगा। लॉजिस्टिक्स की लागत, बंदरगाहों की दक्षता, बिजली की कीमत, वित्त की उपलब्धता, गुणवत्ता मानक, अनुसंधान एवं विकास और उत्पादन की गति—इन सभी क्षेत्रों में सुधार भारतीय उत्पादों को वैश्विक बाजार में मजबूत बना सकता है।

निर्यातकों के लिए सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रोत्साहन और कर-शुल्क वापसी की व्यवस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में सरकार द्वारा ऋशष्टअ्रश्वक्क जैसी निर्यात प्रोत्साहन व्यवस्था को आगे जारी रखने की संभावना पर भी चर्चा हुई है। लेकिन दीर्घकालिक समाधान केवल प्रोत्साहन देना नहीं है। भारतीय उद्योग को ऐसी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकसित करनी होगी कि वह टैरिफ के दबाव के बावजूद वैश्विक खरीदारों के लिए आकर्षक बना रहे।

सम्मान करो संपूर्णता से

तुम किसी का सम्मान उसकी ईमानदारी, बुद्धिमत्ता, प्रेम और कार्य कुशलता जैसे सद्गुणों के लिए करते हो परंतु समय के साथ-साथ इन गुणों में परिवर्तन आता है। जिसके कारण तुम उनका सम्मान नहीं कर पाते। तुम केवल सद्गुणों का, महानता का सम्मान करते हो। मैं संपूर्णता से हर एक का सम्मान करता हूं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के लिए मेरा सम्मान कम नहीं होता। सम्मान पाने के लिए किसी को महान होने की आवश्यकता नहीं। जीवन का सम्मान महान बनाता है। दूसरों से सम्मान की अपेक्षा मत करो। यह कमजोर बनाता है। आत्मा का सम्मान करो। तब कोई तुम्हारे आत्म सम्मान को ले नहीं सकता। जब कोई तुम्हें सम्मान देता है, तो इसलिए नहीं कि तुममे कुछ विशेष गुण हैं। यह उनकी महानता और उदारता के कारण है। यदि तुम कहते हो, ईश्वर महान है, यह तुम्हें महान बनाता है। ईश्वर तो महान हैं ही- तुम्हारे कहने से ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तुम किसी को सम्मान देते हो, यह तुम्हारी विशालता दर्शाता है। यदि तुम सबका सम्मान करते हो तो उतना अधिक तुम्हारा मोल है। वह ज्ञानी है, जो सबका सम्मान करता है। सम्मान देना उन्नत चेतना का गुण है। आत्मा के प्रति सम्मान निष्ठा है और निष्ठा है उन्मुक्त होना। जिस प्रकार तुम मुझे सम्मान देते हो, उसी तरह सबको सम्मान दो। परंतु जो अपेक्षा तुम सबसे करते हो, वह सबसे मत करो। प्रायः तुम इसका उल्टा करते हो। तुम सबको वह आदर नहीं देते, जो मुझको देते हो पर आशा करते हो कि वे तुम्हें खुशी दें, तुमसे उत्तम व्यवहार करें। जब उनका व्यवहार तुम्हारी अपेक्षानुसार नहीं होता, तब तुम निराश होते हो और उनको दोषी ठहराते हो, उनकी निन्दा करते हो। निन्दा करने से, अभिशाप देने से, तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती है। आशीर्वाद तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाता है। सहनशीलता, धैर्य और विवेक से कुशलतापूर्वक आगे बढ़ो। यदि तुम्हारे आसपास मूर्ख हैं, तो समझो, वे तुम्हें और बुद्धिमान बनाएंगे। तुम कितने केंद्रित हो, यह तुम्हारे आसपास रहने वाले मूर्खों की संख्या से मालूम पड़ता है। मूर्खों को हटाने का प्रयास मत करो। यदि तुम केंद्रित नहीं हो, तो तुममे उनको बर्दाश्त करने का धैर्य नहीं होगा। जब तुम पूर्ण रूप से आत्मस्थित हो, तब पाते हो कि मूर्ख से भी ज्ञान मिल सकता है। वे तुम्हारे ही प्रतिबिम्ब हैं। मूर्ख तुम्हें हताश भी कर सकते हैं, या ज्ञान भी दे सकते हैं, चुनाव तुम्हारा है।

क्या भाजपा चीन के माओवाद से प्रभावित?

(लेखक- सनत जैन)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को दिमागी नक्सली को पहचान और उनसे मुक्ति पाने का जो आह्वान किया था, उसके बाद जो प्रतिक्रिया भाजपा के अंदर देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए बरबस ही माओवाद और हिटलर की यादें ताजा होने लगी हैं। भारत सरकार और गृहमंत्री अमित शाह ने पिछले कुछ महीनो में बार-बार कहा है, कि भारत से नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया से जो रील, विपक्षी पार्टियों, छात्रों और कांग्रेस के खिलाफ जारी हो रही हैं। जिस तरह के आक्रामक विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षियों से निपटने के लिए लाठी, तलवार और एके-47 राइफल का इस्तेमाल कर रही है, वह चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी में सोशल मीडिया की नई टीम बनी है। उसने कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के खिलाफ आक्रामक विज्ञापन की श्रृंखला जारी की है। यह सारे विज्ञापन भाजपा के प्रदेश हैंडल से भी जारी किए जा रहे हैं। इसमें तीन अलग-अलग दौर के हथियारों का उपयोग किया गया है। एक विज्ञापन में भाजपा की सारी प्रदेश इकाइयां लाठी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धुनाई कर रही हैं। एक घेरा है जिसमें कांग्रेस बीच में खड़ी है, चारों तरफ से उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं। दूसरे विज्ञापन की रील में रोम के गुलाम विद्रोह पर बनी फिल्म का दृश्य समाहित किया गया है, जिसमें सारे गुलाम योद्धा हाथ में तलवार लेकर हिंसक अंदाज में हमले के लिए तैयार दिख रहे हैं। तीसरे विज्ञापन में एके-47 और एके-56 राइफल हाथ में लेकर भाजपा समर्थक दिमागी नक्सलों पर हमला कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया ने विपक्षी दलों के लिए जिस तरह की आक्रामकता विज्ञापनों में दिखाई है और भाजपा के प्रदेश हैडिल से वह जारी हो रहे हैं। उसके बाद सारे देश में यह चर्चा होने लगी है, क्या भारतीय जनता पार्टी हिटलर और माओ के रास्ते पर चल पड़ी है? इन तीन विज्ञापनों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसके अलावा भी बहुत सारे विज्ञापन सोशल मीडिया हैंडल से जारी किए गए हैं। इनमें ताकत का प्रदर्शन करते हुए सामान्य नागरिकों और विपक्षी दलों के लिए नफरत का भाव स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। इन विज्ञापनों के जरिए केवल कांग्रेस या विपक्षी दलों को निशाने पर नहीं लिया गया है। इसमें छात्रों और युवाओं को भी निशाने पर लिया गया है। एक विज्ञापन में मिर्जापुर सीरीज के एक दृश्य का इस्तेमाल किया गया है। जिसमें एक सामान्य विद्यार्थी कॉलेज में छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहता है। उसे खलनायक के गुंडे बेटे द्वारा जबरिया रोका जाता है। यह गुंडे का लड़का क्लास रूम में आकर छात्र की पिटाई करता है, वह कहता है, तुम क्यों चुनाव लड़ना चाहते हो। भाजपा ने पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से नई विज्ञापन सीरीज जारी की है, उसमें मारकाट और ताकत के बल पर सत्ता करने का जो मनसूबा दिखाई दे रहा है, वह काफी डरावना और भयभीत करने वाला है। भाजपा ने राजनीतिक लड़ाई में जिस तरह से विज्ञापनों के जरिए संदेश प्रसारित करने के लिए हिंसा और अराजकता का रास्ता चुना है, वह भारतीय संदर्भ में आश्चर्यजनक है। भाजपा के सोशल मीडिया ने जिस तरह से सोनिया गांधी, अखिलेश यादव एवं और अन्य नेताओं के खिलाफ अश्लील और अपमानजनक कंटेंट तैयार किए हैं, भारत की जनता उसे स्वीकार करेगी या नहीं, यह कहना भी बड़ा मुश्किल है। भारत में इस तरह की नफरत और हिंसा वाले विज्ञापन, जो भाजपा हैंडल से सीरियल के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, उसने आम लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की मानसिकता का कोई स्थान नहीं है। अगले साल पांच राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं। युवा नाराज होकर सड़कों पर हैं। सारे विपक्षी दल सड़कों पर आकर आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भाजपा का सोशल मीडिया क्या करना चाहता है, भाजपा की मंशा क्या है, इसको लेकर अब आम आदमी में चिंता दिखने लगी है। भारत की संस्कृति इस तरह की नहीं है, जनता इस तरह से भय और दबाव में आकर कोई निर्णय लेगी? अंग्रेजों के शासन में जब भारत पूरा बंटा हुआ था। अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी ताकत थी। उसके बाद भी भारत के गरीब आदिवासी, दलित और सामान्य वर्ग के लोग सड़कों पर आकर लाठी डंडे खाकर भी उन्होंने ना तो अपनी सभ्यता खोई और ना ही वह डरे, अंतोगत्वा अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना ही पड़ा। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस परिस्थिति में विचार करने की जरूरत है। भाजपा का वर्तमान सोशल मीडिया जिस तरह से विज्ञापन प्रकाशित कर रहा है। उसकी प्रतिक्रिया होना भी शुरू हो गई है। कुछ लोग तो यह भी कहने लगे हैं, जिस तरह की स्थिति 1947 और 48 के बीच में देश में देखने को मिली थी। एक बार फिर वही यादें ताजा हो रही हैं। विपक्षी दलों एवं छात्रों ने भी जिस तरह की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया एवं जवाबी तौर पर दी जा रही है, उससे चिंता बढ़ गई है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

एलिवेट कैंपस का आईपीओ 23 सितंबर को खुलेगा

नई दिल्ली ।

एलिवेट कैंपस लिमिटेड का 2,100 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 23 सितंबर को खुलेगा। इसके लिए मूल्य दायरा 343-362 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ दस्तावेजों के अनुसार तीन दिन का सार्वजनिक निर्गम 25 सितंबर को बंद होगा। शेयर के 30 सितंबर को बाजार में सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। आईपीओ में पूरी तरह नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसमें बिक्री पेशकश (ओएफएस) का कोई घटक नहीं है। कंपनी उच्च शिक्षा संस्थानों में परिसर के भीतर छात्र आवास सुविधाओं का स्वामित्व, संचालन और प्रबंधन करती है। इसके पास के-12 शिक्षा से जुड़ी परिसंपत्तियां भी हैं।एलिवेट कैंपस अपने मंच के जरिये संस्थानों को छात्र आवास, भोजन, सुरक्षा और परिसर संचालन सहित एकीकृत गैर-शैक्षणिक सेवाएं उपलब्ध कराती है।निर्गम से प्राप्त राशि का इस्तेमाल के-12 संस्थाओं और परिसरों के अधिग्रहण, कर्ज चुकाने और सामान्य कारोबारी जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा।

सरकारी बैंकों के विलय का वायरल दावा फर्जी, सरकार ने लोगों को किया सतर्क

पीआईबी फैक्ट चेक ने 9 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के तीन बड़े बैंकों में विलय संबंधी दस्तावेज को बताया नकली

नई दिल्ली ।

सोशल मीडिया पर इन दिनों सरकारी बैंकों के विलय से जुड़ा एक दस्तावेज तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार ने 9 पब्लिक सेक्टर बैंक्स (पीएसबी) को तीन बड़े बैंकों - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाने का फैसला किया है। हालांकि, केंद्र सरकार ने इस दावे को फर्जी बताया है और लोगों को ऐसी भ्रामक खबरों से सतर्क रहने को कहा है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस वायरल दस्तावेज की जांच के बाद इसे फर्जी करार दिया है। पीआईबी के अनुसार, यह दस्तावेज वित्त मंत्रालय ने जारी नहीं किया है। दरअसल, दो पेज के इस नकली गजट में दावा किया गया था कि इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मिलाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप बनाया जाएगा। इसी तरह, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में, जबकि केनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय करने की बात कही गई थी। सरकार ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर मिलने वाली ऐसी खबरों पर तुरंत भरोसा न करें। किसी भी सरकारी फैसले की जानकारी के लिए आधिकारिक और भरोसेमंद स्रोतों को ही देखें। फिलहाल ग्राहकों को अपने बैंक खाते, जमा पैसे या बैंकिंग सेवाओं को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

सोना 84 रुपए और चांदी 1170 रुपए महंगी

सोना 1,53,065 प्रति 10 ग्राम, चांदी 2,39,375 रुपए प्रति किलोग्राम

नई दिल्ली ।

भारतीय वायदा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल दर्ज किया गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोना 84 रुपये चढ़कर 1,53,065 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 1170 रुपये की तेजी के साथ 2,39,375 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। कमजोर अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी ने घरेलू मांग को बढ़ावा दिया। अंतरराष्ट्रीय कॉमैक्स बाजार में सोना हल्की गिरावट के साथ 4397 डॉलर प्रति औंस पर रहा, जबकि चांदी 0.63 फीसदी उछलकर 66.51 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। कच्चे तेल की कीमतों में लगभग एक फीसदी की गिरावट और डॉलर के हालिया उच्च स्तर से नीचे आने से सोने को समर्थन मिला है। डॉलर के कमजोर होने से विदेशी खरीदारों के लिए सोना सस्ता हो जाता है, जिससे इसकी मांग बढ़ती है। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के आगामी फैसलों पर भी बाजार की नजर है। प्रमुख भारतीय शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत चेन्नई, मुंबई सहित कई प्रमुख शहरों में 15,283 रुपये प्रति ग्राम रही, जबकि दिल्ली में यह 15,298 रुपये प्रति ग्राम थी। 22 कैरेट सोने का भाव अधिकांश शहरों में 14,009 रुपये प्रति ग्राम दर्ज किया गया, वहीं दिल्ली में 14,024 रुपये प्रति ग्राम रहा। 18 कैरेट सोने की दरें चेन्नई में 11,779 रुपये और दिल्ली में 11,482 रुपये प्रति ग्राम थीं।

मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाया, 7 फीसदी तक पहुंचने की उम्मीद

वैश्विक झटकों के बीच अर्थव्यवस्था ने दिखाई मजबूती; तेल की ऊंची कीमतें और अल नीनो बन सकते हैं चुनौती

नई दिल्ली ।

मूडीज रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर सात प्रतिशत कर दिया है, जो पहले छह प्रतिशत था। रेटिंग एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष जैसे वैश्विक झटकों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया है। हालांकि, उसने तेल की ऊंची कीमतों और अल नीनो के असर से महंगाई बढ़ने के संभावित जोखिमों के प्रति आगाह भी किया है। इस वृद्धि के पीछे मजबूत निजी खपत, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर लगातार हो रहा खर्च, और सेवा क्षेत्र का निरंतर बेहतर प्रदर्शन प्रमुख कारण हैं। मूडीज के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2026 के पहले छह महीनों में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि सालाना आधार पर बढ़कर 8.2 प्रतिशत दर्ज की गई, जो मजबूत आर्थिक गति का संकेत देती है। एजेंसी ने निजी क्षेत्र के निवेश में संभावित सुधार को भी सकारात्मक माना है। हालांकि, मूडीज ने कुछ जोखिमों के प्रति भी आगाह किया है। एजेंसी ने कहा कि यदि पश्चिम एशिया में संघर्ष जारी रहता है, तो तेल की ऊंची कीमतें वित्त वर्ष 2026-27 में औसत मुद्रास्फीति को उसके 4.8 प्रतिशत के अनुमान से ऊपर ले जा सकती हैं। इसके अलावा, अल नीनो के प्रभाव से खाद्य कीमतों पर दबाव बढ़ने और निजी खपत व आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक असर पड़ने की आशंका है। एजेंसी ने देश पर कर्ज के उच्च बोझ और ब्याज लागत को भी कर्ज चुकाने की क्षमता के लिए धीमी चुनौती बताया है। इन चुनौतियों के बावजूद भारत के कच्चे तेल आयात स्रोतों का विविधीकरण और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। मूडीज ने यह भी उम्मीद जताई है कि भारत अन्य जी20 देशों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ेगा। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में जापान की जेसीआर ने भी 35 साल बाद भारत की रेटिंग को ए- तक बढ़ाया था, जो देश की मजबूत आर्थिक स्थिति का एक और प्रमाण है। आरबीआई के अनुमान से अधिक, वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी थी।

कच्चे तेल में तीसरे दिन भी नरमी

ब्रेंट क्रूड आयल 104 डॉलर के नीचे

नई दिल्ली ।

कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में शुक्रवार गिरावट दर्ज की गई। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बावजूद, सऊदी अरब से तेल आपूर्ति में संभावित व्यवधान की आशंका कम होने से बाजार को राहत मिली है। शुरुआती कारोबार में ब्रेंट क्रूड लगभग 1 फीसदी गिरकर 103.77 डॉलर प्रति बैरल जबकि अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड 100.88 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस गिरावट की मुख्य वजह सऊदी अरब की ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन की आधी क्षमता जल्द बहाल होने की उम्मीद है। पिछले सप्ताह ड्रोन हमले के बाद इस पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा था, जिससे आपूर्ति प्रभावित होने का डर था।

साथ ही, सऊदी अरब ओमान के सोहर बंदरगाह के जरिए एशियाई खरीदारों को वैकल्पिक रास्ते से तेल पहुंचा रहा है, जिससे बाजार में तेल की कमी का खतरा कुछ कम हुआ है। हालांकि, पश्चिम एशिया में तनाव बरकरार है, लेकिन बाजार का ध्यान अब वास्तविक तेल आपूर्ति पर है। पिछली तेजी के बाद मुनाफावसूली भी हुई है।

ब्रेंट क्रूड अभी भी 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर है, और आपूर्ति जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगर पाइपलाइन की मरम्मत में देरी हुई या क्षेत्र में कोई नया बड़ा हमला हुआ तो कीमतें फिर से तेजी पकड़ सकती हैं।

भारतीय उत्पादों का ग्लोबल फेस्टिवल, घरेलू बिक्री 5 साल के शिखर पर

त्योहारी रौनक ने खाद्य उत्पाद, वस्त्र और हस्तशिल्प की मांग बढ़ाई

नई दिल्ली ।

गणेशोत्सव से शुरू हुए त्योहारी सीजन ने घरेलू बाजारों में खरीदारी का उत्साह पांच साल के उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है। साथ ही, दुनिया भर में भारतीय उत्पादों की बढ़ती मांग ने निर्यात को भी नया आयाम दिया है। देश में मिठाई, कपड़े और सजावटी सामान की बिक्री में तेजी है। वहीं, अमेरिका, यूरोप, खाड़ी देशों और भारतीय प्रवासी बहुल बाजारों में भारतीय स्वाद, संस्कृति और उत्पादों, जैसे खाद्य पदार्थ, पारंपरिक परिधान और हस्तशिल्प की मांग में भारी इजाफा हुआ है। अगस्त में भारत का माल निर्यात 26 फीसदी बढ़कर 43.8 बिलियन डॉलर रहा, जिसमें त्योहारी ऑर्डर और अमेरिकी मांग ने अहम भूमिका निभाई। यूरोप में भारतीय खाद्य उत्पादों के ऑर्डर 20 फीसदी तक बढ़े हैं, जबकि अमेरिका में टेक्सटाइल और तैयार कपड़ों के ऑर्डरों में 30-40 फीसदी तक की वृद्धि दर्ज की गई है। क्लोदिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सर्वे के अनुसार, 52 फीसदी परिधान निर्माताओं को बेहतर बिक्री की उम्मीद है। मावा की मिठाइयों की मांग 145 फीसदी बढ़ी है, जिसमें खाड़ी देश एक प्रमुख बाजार के रूप में उभरे हैं। कुवैत, ओमान और बहरीन में मिठाइयों, ड्राइ फ्रूट्स, नमकीन और मसालों की लगातार खरीद हो रही है। विशेषज्ञों के अनुसार, वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं और चीन पर निर्भरता कम होने से भारतीय निर्यातकों को नए अवसर मिल रहे हैं। छोटे शहरों में भी कारोबार तेज होने से समग्र बाजार भावना सकारात्मक बनी हुई है।

शेयर बाजार मिले-जुले रुख के साथ बंद

सेंसेक्स 19 अंक गिरा, निफ्टी 75 अंक उछला

मुंबई

घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को मिले-जुले रुख के साथ बंद हुआ। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन दुनिया भर के बाजारों से कमजोर संकेतों और आईटी शेयरों में गिरावट से बाजार उठ नहीं पाया। आज केवल व्यापक बाजार ने ही बाजार में गिरावट पर अंकुश लगाये रखा। बेंचमार्क इंडेक्स दिनभर एक सीमित दायरे में कारोबार करते नजर आए।

दिन भर के कारोबर के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स

19.63 अंक नीचे आकर 74,294.96 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 75.80 अंक की बढ़त लेकर 23,346.40 के स्तर पर बंद हुआ। .

यह पहली बार है जब निफ्टी 23,300 के मनोवैज्ञानिक स्तर के ऊपर बंद हुआ है। आज कारोबार में छोटे और मझोले शेयरों का प्रदर्शन अच्छा रहा। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स में 1.24 फीसदी और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स में 1.74 फीसदी की तेजी दर्ज की गई।

आज दिग्गज शेयरों में खरीदारी भी रही। निफ्टी पर अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेज और भारती एयरटेल सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाले शेयरों में शामिल रहे.

वहीं मेटल, रियलिटी, ऑयल एंड गैस, सीमेंट और केमिकल सेक्टर्स में आज सबसे ज्यादा तेजी रही। . कच्चे तेल की कीमतों में नरमी और वैश्विक बॉन्ड यील्ड में गिरावट से इन क्षेत्रों को सहारा मिला जबकि आईटी सेक्टर में

आज सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई और यह बाजार पर दबाव बनाने का काम करता रहा। वहीं इससे पहले आज सुबह बाजार में तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। वैश्विक संकेतों और तेल की कीमतों में कमी आने से प्रमुख सूचकांकों को सहारा मिला और वे हरे निशान पर खुल गए, जिससे निवेशकों में उत्साह देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 165.37 अंकों की बढ़त के साथ 74,479.96 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी भी 52.35 अंक बढ़कर 23,322.95 पर खुला।

जापान ने भी बढ़ाई ब्याज दर, 31 साल का रिकॉर्ड टूटा

बैंक ऑफ जापान ने मुख्य दर बढ़ाकर 1.25 फीसदी की

नई दिल्ली ।

जापान के केंद्रीय बैंक, बैंक ऑफ जापान ने महंगाई पर लगाम लगाने और अपनी कमजोर मुद्रा येन को सहारा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। शुक्रवार को बैंक ने अपनी मुख्य ब्याज दर में 0.25 फीसदी की बढ़ोतरी करते हुए इसे 1.25 फीसदी कर दिया। यह पिछले 31 सालों में जापान में ब्याज दर का सबसे उच्चतम स्तर है, जो अंतिम बार 1995 में इस स्तर पर थी। यह फैसला ऐसे समय आया है जब वैश्विक ऊर्जा संकट, ईरान युद्ध और घरेलू चुनौतियों से जापान की अर्थव्यवस्था जूझ रही है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती महंगाई और विशेषकर ईरान युद्ध के कारण कच्चे तेल व गैस की कीमतों में आए उछाल ने जापान पर भारी दबाव डाला है। जापान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पश्चिम एशिया पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य में व्यवधान का सीधा असर उस पर पड़ता है। देश पहले से ही तीनहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है - लगातार कमजोर होता येन, बढ़ती कीमतें और घटता कार्यबल। ऊर्जा महंगी होने से जापान का आयात बिल बढ़ रहा है, जिसका सीधा बोझ आम लोगों पर पड़ने की आशंका है। लंबे समय तक जापान अपनी बेहद कम ब्याज दरों के लिए जाना जाता था, जहां दशकों तक कीमतों में गिरावट (डिफ्लेशन) एक बड़ी समस्या थी। बैंक ऑफ जापान ने 2024 तक (नकारात्मक -0.1 फीसदी) जैसी बेहद कम दरों पर भी काम किया है। हालांकि, अब हालात बदल रहे हैं; पिछले ढाई सालों में बैंक ने छह बार दरें बढ़ाई हैं, जो अब 1.25 फीसदी पर पहुंच गई हैं। यह दिखाता है कि देश अब बढ़ती कीमतों की नई चुनौती का सामना कर रहा है। हालिया सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त में जापान की मुख्य महंगाई दर 1.7 फीसदी रही, जो जुलाई के 1.8 फीसदी से थोड़ी कम है, लेकिन बैंक ऑफ जापान के 2 फीसदी के लक्ष्य के करीब बनी हुई है। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले जापान में महंगाई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जापान के लिए लगातार बढ़ती कीमतें पिछले कुछ दशकों के मुकाबले एक बड़ा बदलाव हैं। जापानी येन पिछले कई महीनों से दबाव में है और अगस्त में यह 40 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया था। येन की गिरावट को रोकने के लिए जापान और अमेरिका को बाजार में संयुक्त हस्तक्षेप करना पड़ा था। आम तौर पर किसी देश में ब्याज दर बढ़ने से उसकी मुद्रा को मजबूती मिलती है क्योंकि विदेशी निवेशकों के लिए वहां निवेश करना अधिक आकर्षक हो जाता है।

रुपया गिरावट के साथ बंद

मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया शुक्रवार को दो पैसे की गिरावट के साथ ही 95.93 पर बंद हुआ। रुपया शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में 16 पैसे की बढ़त के साथ ही 95.73 प्रति डॉलर पर पहुंच गया। घरेलू शेयर बाजारों में खरीदारी और विदेशी बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से घरेलू मुद्रा को समर्थन मिला। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि इस सप्ताह की शुरुआत में तेज बढ़ोतरी के बाद कच्चे तेल की कीमतों के 104 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आने से भारतीय मुद्रा पर दबाव कम हुआ। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल भी रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 95.75 प्रति डॉलर पर खुला। शुरुआती कारोबार में थोड़ा मजबूत होकर 95.73 प्रति डॉलर पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 16 पैसे की बढ़त है। रुपया गुरुवार को दो पैसे मजबूत होकर 95.91 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था।

सिंगापुर-भारत व्यापार को नई दिशा देगा एसआईसीसीआई- मेनन

सिंगापुर ।

सिंगापुर इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसआईसीसीआई) के नवनियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) प्रदीप मेनन ने संगठन की नई रणनीतिक रूपरेखा का अनावरण किया है। इसके तहत एसआईसीसीआई भारत सरकार, नीति निर्माताओं और उद्योग जगत के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत करने की योजना बना रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ करना और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देना है। मेनन ने बताया कि अगले तीन से छह महीनों में, एसआईसीसीआई भारत के नेताओं, नीति-निर्माताओं और उद्योग जगत के लोगों के साथ अपने संबंधों को और गहरा करेगा।

संगठन प्रमुख भारतीय राज्यों में लक्षित व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी भेजेगा, जिसकी शुरुआत तमिलनाडु से होगी, ताकि सिंगापुर स्थित कंपनियों के लिए नए कारोबारी अवसर खोले जा सकें। उन्होंने दोनों देशों के बीच पारस्परिक लाभ वाले संबंध पर जोर दिया।

मेनन के अनुसार भारतीय कंपनियों को सिंगापुर से कारोबार की उत्पादकता बढ़ाने वाली विशेषज्ञता मिलती है, जबकि सिंगापुर की कंपनियों को भारत के विशाल उपभोक्ता बाजार और प्रतिभा के बड़े समूह तक पहुंच मिलती है। उन्होंने यह भी बताया कि भारत सिंगापुर के लिए मानव संसाधन का एक प्रमुख स्रोत है, जो प्रतिभा की कमी को पूरा करने में महत्वपूर्ण है। एसआईसीसीआई का लक्ष्य क्षेत्रीय पूंजी के लिए सिंगापुर की भरोसेमंद भूमिका को भी मजबूत करना है, विशेष रूप से आसियान निवेशकों के लिए जो भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था में पारदर्शी निवेश करना चाहते हैं। मेनन ने पिछले महीने ही एसआईसीसीआई के सीईओ का पद संभाला है; वह 2003 से 2010 तक भी इस पद पर रह चुके हैं।

सत्य नडेला ने सराही भारत-अमेरिका प्रौद्योगिकी साझेदारी, एआई पर दिया जोर

सिएटल में आइडियाज4इंडिया फोरम में 40 से अधिक भारतीय मूल के टेक सीईओ और सीटीओ हुए शामिल

न्यूयॉर्क ।

माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और सीईओ सत्य नडेला ने सिएटल में भारतीय-अमेरिकी प्रौद्योगिकी समुदाय और भारत के साथ इसके बढ़ते मजबूत संबंधों की सराहना की। उन्होंने कृत्रिम मेधा (एआई) को एक ऐसी सामान्य उपयोग वाली प्रौद्योगिकी बताया, जिसके लाभ इसके व्यापक अपनाने पर निर्भर करेंगे। सिएटल में भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजित आइडियाज4इंडिया- इंडियन अमेरिकन टेक सीईओ फोरम- अनलॉकिंग द टेक डिविडेंड कार्यक्रम में नडेला ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर भारतीय मूल के सीईओ को संबोधित किया।

उन्होंने पिछले 35 वर्षों में सिएटल के प्रौद्योगिकी समुदाय की प्रगति और भारत के साथ उसके संबंधों के सुदृढ़ीकरण पर गर्व व्यक्त किया। इस अवसर पर अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने भारतीय मूल के सीईओ तथा कार्यक्रम के अन्य प्रतिभागियों की भारत-अमेरिका प्रौद्योगिकी साझेदारी को और गहरा करने की मजबूत इच्छा का स्वागत किया। क्वात्रा ने दोहराया कि भारत का एआई मिशन समावेशिता, खुलेपन, संप्रभुता, सभी के लिए समान पहुंच, सुरक्षा और भरोसे के सिद्धांतों पर मजबूती से आधारित रहेगा। इस विशेष कार्यक्रम में माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, बोइंग, ओपनएआई, एंथ्रोपिक और इंटेल जैसी प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों के 40 से अधिक भारतीय मूल के सीईओ और सीटीओ शामिल हुए। इनमें से कई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों जैसे एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक समय से कार्यरत हैं।

भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा मजबूत- टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स

गुजरात और असम में 14 अरब डॉलर की परियोजनाएं ट्रैक पर

नई दिल्ली ।

टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के एक प्रमुख अे धिकारी ने घोषणा की है कि भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा बेहद मजबूत दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने सेमीकॉन 2.0 के तहत मिली नीतिगत स्थिरता को उद्योग के लिए महत्वपूर्ण बताया, जिससे कार्ययोजना में महत्वपूर्ण निरंतरता बनी हुई है। भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में अपनी मजबूत जगह बनाने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रहा है और इस प्रयास में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अे धिकारी ने सेमीकॉन इंडिया के मौके पर कहा कि हमारे कारोबार में निरंतरता महत्वपूर्ण है और सेमीकंडक्टर एक कार्ययोजना आधारित यात्रा है। सेमीकंडक्टर 1.0 योजना के बाद सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर 2.0 लाना उत्साहजनक है, जो इस क्षेत्र के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है। उन्होंने जोर दिया कि जैसे-जैसे कंपनी नकदी प्रवाह उत्पन्न करेगी, वह लगातार निवेश करती रहेगी और इस यात्रा को आगे बढ़ाएगी। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात के धोलेरा में भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण संयंत्र (फैब) स्थापित कर रहा है, जिसमें 91,000 करोड़ रुपये (लगभग 11 अरब डॉलर) का निवेश किया जा रहा है। यह संयंत्र 28 नैनोमीटर से 110 नैनोमीटर तक की प्रौद्योगिकी नोड पर चिप बनाएगा, जिनका उपयोग वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटिंग और कृत्रिम मेधा (एआई) जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होगा। इसके अतिरिक्त, कंपनी असम के जागीरोड में देश की पहली स्वदेशी सेमीकंडक्टर असेंबली एवं परीक्षण सुविधा के लिए तीन अरब डॉलर का निवेश कर रही है। दोनों परियोजनाओं में कुल 14 अरब डॉलर का निवेश किया जा रहा है, जिनका उद्देश्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वैश्विक ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना है। उन्होंने पुष्टि की कि धोलेरा का विनिर्माण संयंत्र और जागीरोड की पैकेजिंग सुविधा दोनों सरकार के साथ तय समयसीमा के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। सेमीकॉन इंडिया के दौरान टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा हस्ताक्षरित 16 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का उद्देश्य उपकरण, बुनियादी ढांचा, गैस एवं रसायन तथा प्रतिभा विकास सहित एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है।

टाटा संस पर आरबीआई फैसले का शापूर मिस्त्री ने किया स्वागत

- मिस्त्री ने कहा- यह कदम कंपनी में जवाबदेही बढ़ाएगा, शेयरधारकों और ट्रस्ट के बीच बनेगा पुल

नई दिल्ली ।

शापूरजी पल्लोनजी समूह के चेयरमैन शापूर मिस्त्री ने टाटा संस को अपर-लेयर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (बीएफसी) के नियमों के तहत लाने के भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के फैसले का स्वागत किया है। मिस्त्री ने इस कदम को टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी में पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण बताया, जिससे इसके सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। उनके परिवार के स्वामित्व वाले शापूरजी पल्लोनजी समूह की टाटा संस में लगभग 18.4 प्रतिशत हिस्सेदारी है। आरबीआई ने 11 सितंबर को टाटा संस के प्रमुख निवेश कंपनी के रूप में पंजीकरण वापस लेने के आवेदन को खारिज कर दिया था और उसे नियामक ढांचे का पालन करने का निर्देश दिया था। इस फैसले से वर्षों से निजी स्वामित्व वाली कंपनी का दर्जा बनाए रखने के प्रयासों के बाद, अब टाटा संस के सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध होने का रास्ता खुल गया है। मिस्त्री ने जोर देकर कहा कि इस महत्वपूर्ण फैसले को किसी एक हिस्सेदार की दूसरे पर जीत के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टाटा संस की सूचीबद्धता शेयरधारकों और टाटा ट्रस्ट्स के बीच तथा निजी स्वामित्व एवं सार्वजनिक जवाबदेही के बीच एक सेतु बन सकती है। मिस्त्री ने आगे कहा कि सूचीबद्धता से होल्डिंग कंपनी के मूल्य के बारे में अधिक जानकारी मिलेगी, व्यावसायिक कामकाज मजबूत होगा और टाटा ट्रस्ट्स की परोपकारी गतिविधियों के लिए मूल्य का अधिक टिकाऊ प्रवाह सुनिश्चित होगा।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

हजारों वर्षों से विश्वभर में मशरूमों की उपयोगिता भोजन और औषध दोनों ही रूपों में रही है। ये पोषण का भरपूर स्रोत हैं और स्वास्थ्य खाद्यों का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। मशरूमों में वसा की मात्रा बिल्कुल कम होती हैं, विशेषकर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, और इस वसायुक्त भाग में मुख्यतया लिनोलिक अम्ल जैसे असंतप्तिकृत वसायुक्त अम्ल होते हैं, ये स्वस्थ हृदय और हृदय संबंधी प्रक्रिया के लिए आदर्श भोजन हो सकता है। पहले, मशरूम का सेवन विश्व के विशिष्ट प्रदेशों और क्षेत्रों तक ही सीमित था पर वैश्वीकरण के कारण विभिन्न संस्कृतियों के बीच संप्रेषण और बढ़ते हुए उपभोक्तावाद ने सभी क्षेत्रों में मशरूमों की पहुंच को सुनिश्चित किया है। मशरूम तेजी से विभिन्न पाक पुस्तक और रोजमर्रा के उपयोग में अपना स्थान बना रहे हैं। एक आम आदमी को रसोई में भी उसने अपनी जगह बना ली है। उपभोग की चालू प्रवृत्ति मशरूम निर्यात के क्षेत्र में बढ़ते अवसरों को दर्शाती है।

मशरूम की खेती

मशरूम की उपयोगिता

भारत में मशरुम की खेती-आम प्रजातियां

भारत में उगने वाले मशरूम की दो सर्वाधिक आम प्रजातियां वाईट बटन मशरूम और ऑयस्टर मशरूम है। हमारे देश में होने वाले वाईट बटन मशरूम का ज्यादातर उत्पादन मौसमी है। इसकी खेती परम्परागत तरीके से की जाती है। सामान्यता, अपॉश्चयरीकृत कूड़ा खाद का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उपज बहुत कम होती है। तथापि पिछले कुछ वर्षों में बेहतर कृषि-विज्ञान पदधातियों की शुरूआत के परिणामस्वरूप मशरूमों की उपज में वृद्धि हुई है। आम वाईट बटन मशरूम की खेती के लिए तकनीकी कौशल की आवश्यकता है। अन्य कारकों के अलावा, इस प्रणाली के लिए नमी चाहिए, दो अलग तापमान चाहिए अर्थात पैदा करने के लिए अथवा प्ररोहण वृद्धि के लिए (स्पॉन रन) 220-280 डिग्री से, प्रजनन अवस्था के लिए (फल निर्माण) ः 150-180 डिग्री से; नमीः 85-95 प्रतिशत और पर्याप्त संवातन सब्स्ट्रेट के दौरान मिलना चाहिए जो विसंक्रमित हैं और अत्यंत रोगाणुरहित परिस्थिति के तहत उगाए न जाने पर आसानी से संदूषित हो सकते हैं। अतः 100 डिग्री से. पर वाष्पन (पास्तुरीकरण) अधिक स्वीकार्य है।

प्लयूरोटस, ऑएस्टर मशरूम का वैज्ञानिक नाम है। भारत के कई भागों में, यह ढींगरी के नाम से जाना जाता है। इस मशरूम की कई प्रजातिया है उदाहणार्थ :- प्लयूरोटस ऑस्टरीयटस, पी सजोर-काजू, पी.फ्लोरिडा, पी.सैपीडस, पी.फ्लैबेलैटस, पी एरीनजी तथा कई अन्य भोज्य प्रजातियां। मशरूम उगाना एक ऐसा व्यवसाय है, जिसके लिए अध्यवसाय धैर्य और बुद्धिसंगत देख-रेख जरूरी है और ऐसा कौशल चाहिए जिसे केवल बुद्धिसंगत अनुभव द्वारा ही विकसित किया जा सकता है।

प्लयूरोटस मशरूमों की प्ररोहण वृद्धि (पैदा करने का दौर) और प्रजनन चरण के लिए 200-300 डिग्री का तापमान होना चाहिए। मध्य समुद्र स्तर से 1100-1500 मीटर की ऊचांई पर उच्च तुंगता पर इसकी खेती करने का उपयुक्त समय मार्च से अक्तूबर है, मध्य समुद्र स्तर से 600-1100 मीटर की ऊचांई पर मध्य तुंगता पर फरवरी से मई और सितंबर से नवंबर है और समुद्र स्तर से 600 मीटर नीचे की निम्न तुंगता पर अक्तूबर से मार्च है।

आवश्यक सामान

1. धान के तिनके - फफूंदी रहित ताजे सुनहरे पीले धान के तिनके, जो वर्षा से बचाकर किसी सूखे स्थान पर रखे गए हो।
2. 400 गेज के प्रमाप की मोटाई वाली प्लास्टिक शीट - एक ब्लाक बनाने के लिए 1 वर्ग मी. की प्लास्टिक शीट चाहिए।
3. लकड़ी के सांचे - 45ग्30ग्15 से. मी. के माप के लकड़ी के सांचे, जिनमें से किसी का भी सिरा या तला न हो, पर 44ग्29 से. मी. के आयाम का एक अलग लकड़ी का कवर हो।
4. तिनकों को काटने के लिए गंडासा या भूसा कटर।
5. तिनकों को उबालने के लिए ड्रम (कम से कम दो)
6. जूट की रस्सी, नारियल की रस्सी या प्लास्टिक की रस्सियां
7. टाट के बोरे 8. स्पान अथवा मशरूम जीवाणु जिन्हें सहायक रोगविज्ञानी, मशरूम विकास केन्द्र, से प्रत्येक ब्लॉक के लिए प्राप्त किया जा सकता है।
9. एक स्प्रेयर 10. तिनकों के भंडारण के लिए शेड 10ग्8 मी. आकार का।

स्पानिंग

प्रक्रिया

कूड़ा खाद तैयार करना

कूड़ा खाद बनाने के लिए अन्न के तिनकों (गेंहू, मक्का, धान, और चावल), मक्कई की डंडिया, गन्ने की कोई जैसे किसी भी कृषि उपोत्पाद अथवा किसी भी अन्य सेल्यूलोस अपशिष्ट का उपयोग किया जा सकता है। गेंहू के तिनकों की फसल ताजी होनी चाहिए और ये चमकते सुनहरे रंग के हो तथा इसे वर्षा से बचा कर रखा गया है। ये तिनके लगभग 5-8 से.मी. लंबे टुकडों में होने चाहिए अन्यथा लंबे तिनकों से तैयार किया गया ढेर कम सघन होगा जिससे अनुचित किण्वन हो सकता है। इसके विपरीत, बहुत छोटे तिनके ढ़ेर को बहुत अधिक सघन बना देंगे जिससे ढ़ेर के बीच तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा जो अनएरोबिक किण्वन में परिणामित होगा। गेंहू के तिनके अथवा उपर्युक्त सामान में से सभी में सूल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस और लिगनिन होता है, जिनका उपयोग कार्बन के रूप में मशरूम कवक वर्धन के लिए किया जाता है। ये सभी कूड़ा खाद बनाने के दौरान माइक्रोफ्लोरा के निर्माण के लिए उचित वायुमिश्रण सुनिश्चित करने के लिए जरूरी सबस्टूटे को भौतिक ढांचा भी प्रदान करता है। चावल और मक्कई के तिनके अत्यधिक कोमल होते है, ये कूड़ा खाद बनाने के समय जल्दी से अवक्रमित हो जाते हैं और गेंहू के तिनकों की अपेक्षा अधिक पानी सोखते हैं। अतः, इन सबस्टूट्स का प्रयोग करते समय प्रयोग किए जाने वाले पानी की प्रमात्रा, उलटने का समय और दिए गए संपूरकों की दर और प्रकार के बीच समायोजन का ध्यान रखना चाहिए। चूंकि कूड़ा खाद तैयार करने में प्रयुक्त उपोत्पादों में किण्वन प्रक्रिया के लिए जरूरी नाइट्रोजन और अन्य संघटक, पर्याप्त मात्रा में नहीं होते, इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए, यह मिश्रण नाइट्रोजन और कार्बोहाइड्रेट्स से संपूरित किया जाता है।

स्पानिंग अधिकतम तथा सामयिक उत्पाद के लिए अंडों का मिश्रण है। अण्डज के लिए अधिकतम खुराक कम्पोस्ट के ताजे भार के 0.5 तथा 0.75 प्रतिशत के बीच होती है। निम्नतर दरों के फलस्वरूप माइसीलियम का कम विस्तार होगा तथा रोगों एवं प्रतिद्वान्द्वियों के अवसरों में वृद्धि होगी उच्चतर दरों से अण्डज की कीमत में वद्धि होगी तथा अण्डज की उच्च दर के फलस्परूप कभी-कभी कम्पोस्ट की असाधारण ऊष्मा हो जाती है।

ए बाइपोरस के लिए अधिकतम तापमान 230 से (+) (-) 20 से./उपज कक्ष में सापेक्ष आर्द्रता अण्डज के समय 85-90 प्रतिशत के बीच होनी चाहिए।

कटाई

थैले को खोलने के 3 से 4 दिन बाद मशरूम प्रिमआर्डिया रूप धारण करना शुरू कर देते हैं। परिपक्व मशरूम अन्य 2 से 3 दिनों में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। एक औसत जैविक कारगरहा (काटे गए मशरूम का ताजा भार जिसे एयर ड्राई सबट्रेट द्वारा विभक्त किया गया हो ङ्ग100) 80 से 150 प्रतिशत के बीच हो सकती है और कभी-कभी उससे ज्यादा। मशरूम को काटने के लिए उन्हें जल से पकड़ा जाता है तथा हल्के से मरोड़ा जाता है तथा खींच लिया जाता है। चाकू का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मशरूम रेफ्रीजेरेटर में 3 से 6 दिनों तक जाता बना रहता है।

मशरूम गृह/कक्ष

क्यूब तैयार करने का कक्ष

एक आदर्श कक्ष आर.सी.सी. फर्श का होना चाहिए, रोशनदानयुक्त एवं सूखा होना चाहिए। लकड़ी के ढांचे को रखने, क्यूब एवं अन्य आर.सी.सी. चबूतरा के लिए कक्ष के अंदर 2 सेमी ऊंचा चबूतरा बनाया जाना चाहिए, ऐसा भूसे के पाश्चुरीकृत थैलों को बाहर निकालने की आवश्यतानुसार होना चाहिए। जिन सामग्रियों के लिए क्यूब को बनाने की आवश्यकता है, उन्हें कक्ष के अंदर रखा जाना चाहिए। क्यूब को तैयार करने वाले व्यक्तियों को ही कमरे के अंदर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

उठमायन कक्ष

उण्डजों के संचालन के लिए कमरा यह कमरा आरसीसी भवन अथवा आसाम विस्म (घर में कोई अलग कमरा) का कमरा होना चाहिए तथा खण्डों को रखने के लिए तीन स्तरों में साफ छेद वाले बांस की आलमारी लगाई जानी चाहिए। पहला स्तर जमीन से 100 सेमी ऊपर होना चाहिए तथा दूसरा स्तर कम से कम 60 सेमी ऊंचा होना चाहिए।

फसल कक्ष

एक आदर्श गृह/कक्ष आर.सी.सी. भवन होगा जिसमें विधिवत उष्मारोधन एवं कक्ष को ठंडा एवं गरम करने का प्रावधान स्थापित किया गया होगा। तथापि बांस, थप्पर तथा मिट्टी प्लास्टर जैसे स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का इस्तेमाल करते हुए स्वदेशी अल्प लागत वाले घर की सिफारिश की गई है। मिट्टी एवं गोबर के समान मिश्रण वाले स्पिलिट बांस की दीवारें बनाई जा सकती है।

कच्ची ऊष्मारोधक प्रणाली का प्रावधान करने के लिए घर के चारों ओर एक दूसरी दीवार बनाई जाती है जिसमें प्रथम एवं दूसरी दीवार के मध्य 15 सेमी का अंतर रखा जाता है। बाहरी दीवार के बाहरी तरफ मिट्टी का पलास्टर किया जाना चाहिए। दो दीवारों के मध्य में वायु का स्थान ऊष्मा रोधक का कार्य करेगा क्योंकि वायु ऊष्मा का कुचालक होती है। यहां तक कि एक बेहतर ऊष्मारोधन का प्रावधान किया जा सकता है यदि दीवारों के बीच के स्थान को अच्छी तरह से सूखे 8 ए छप्पर से भर दिया जाए। घर का फर्श वरीयतः सीमेंट का होना चाहिए किन्तु जहां यह संभव नही है, अच्छी तरह से कूटा हुआ एवं प्लास्टरयुक्त मिट्टी का फर्श पर्याप्त होगा। तथापि, मिट्टी की फर्श के मामले में अधिक सावधानी बरतनी होगी। छत मोटे छापर की तहो अथवा वरीयतः सीमेंट की शीटों की बनाई जानी चाहिए। छप्पर की छत से अनावश्यक सामग्रियों के संदूषण से बचने के लिए एक नकली छत आवश्यक है। प्रवेश द्वार के अलावा, कक्ष में वायु के आने एवं निकलने के लिए कमरे के आयु एंव पश्च भाग के ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ से रोशनदानों का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। घर तथा कक्षा ऊर्ध्वाधर एवं अनुप्रस्थ बांस के खम्भों के ढांचो का होना चाहिए जो ऊष्मायन अवधि के उपरान्त खंडों को टांगने के लिए अपेक्षित है। अनुप्रस्थ खम्भों को ऊष्मायन आलमारी के रूप में 3 स्तरीय प्रणाली में व्यवस्थित किया जा सकता है। खम्भे वरीयतः दीवारों से 60 सेमी दूर तथा तीनों स्तरों की प्रत्येक पंक्ति के बीच में होने चाहिए, 1 सेमी की न्यूनतम जगह बनाई रखी जानी चाहिए। 3.0X2.5X2.0 मी. का फसल कक्ष 35 से 40 क्यूबों को समायोजित करेगा।

विधि

भूसे को हाथ के यंत्र से 3-5 सेमी लम्बे टुकडों में काटिए तथा टाट की बोरी में भर दीजिए। एक ड्रम में पानी उबालिए। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो भूसे के साथ टाट की बोरी को उबलते पानी में रख दीजिए तथा 15-20 मिनट तक उबालिए। इसके पश्चात फेरी को ड्रम से हटा लीजिए तथा 8-10 घंटे तक पड़े रहने दीजिए ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए तथा चोकर को ठंडा होने दीजिए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि ब्लॉक बनाने तक थैले को खुला न छोड़ा जाए क्योंकि ऐसा होने पर उबला हुआ चोकर संदूषित हो जाएगा। हथेलियों के बीच में चोकर को निचोड़कर चोकर की वांछित नमी तत्व का परीक्षण किया जा सकता है तथा सुनिश्चित कीजिए कि पानी की बूंदे चोकर से बाहर न निकलें। चोकर के पाश्चुरीकृत का दूसरा तरीका भापन है। इस तरीके के लिए ड्रम में थोड़े परिवर्तन की आवश्यकता होती है (ड्रम के ढक्कन में एक छोटा छेद कीजिए तथा चोकर को उबालते समय रबर की ट्यूब से ढक्कन के चारों ओर सील लगा दीजिए) टुकड़े-डुकड़े किए गए चोकर को पहले भिगो दीजिए तथा अतिरिक्त पानी निकाल दिया जाए। ड्रम में कुछ पत्थर डाल दीजिए तथा पत्थर के स्तर तक पानी उड़ेलिए। बांस की टोकरी में रखकर गीले चोकर को उबाल दें तथा ड्रम के अंदर पत्थर के ऊपर टोकरी को रख दें। ड्रम के ढक्कन को बंद कर दें तथा रबर की ट्यूब से ढक्कन की नेमि को सील कर दीजिए। उबले हुए पानी से उत्पन्न भाप चोकर से गुजरते हुए इसे पाश्चुरीकृत करेगी। उबालने के बाद चोकर को पहले से कीटाणुरहित किए गए बोरी में स्थानांतरित कर दिजिए तथा 8-10 घंटे तक इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। लकड़ी का एक सांचा लीजिए तथा चिकने फर्श पर रख दीजिए। पटसून की दो रस्सियों ऊर्ध्वाधर एवं अनुप्रस्थ रूप में रख दीजिए। प्लास्टिक की शीट से अस्तर लगाइए जिसे पहले उबलते पानी में डुबोकर कीटाणुरहित किया गया है।

5 सेमी. के उबले चोकर को भर दीजिए तथा लकड़ी के ढक्कन की मदद से इसे सम्पीडित कीजिए तथा पूरी सतह पर स्पान को छिड़किए। स्पानिंग की प्रथम तह के उपरान्त 5 सेमी का अन्य चोकर रखिए तथा सतह पर पुनः स्थान का छिड़काव करें तथा प्रथम तह में किए गए की तरह इसे सम्पीडित कीजिए। इस प्रकार तह पर स्पान को 4 से 6 तह तक के लिए तब तक छिड़किए जब तक चोकर सांचे के शीर्ष के स्तर तक न आ जाए। एक (1) एक पैकेट स्पान का इस्तेमाल 1 क्यूब अथवा ब्लाक के लिए किया जाना चाहिए। अब प्लास्टिक की शीट सांचे की शीर्ष पर मोडी जाए प्लास्टिक के नीचे पहले रखी गई पटसून की रस्सियों से उसे बांध दिया जाए। बांधने के उपरांत सांचे को हटाया जा सकता है तथा चोकर का आयताकर खंड पीछे बच जाता है।

वायु के लिए खंड के सभी तरफ छेद (2 मिमी व्यास) बनायें।

ऊष्मायन कक्ष में ब्लॉक को रख दीजिए उन्हें सरल तह में एक दूसरे के बगल रखा जाए तथा इस बात का ध्यान रखा जाए कि उन्हें फर्श पर अथवा एक दूसरे के शीर्ष पर सीधे न रखा जाए क्योंकि इससे अतिरिक्त ऊष्मा उत्पन्न होगी।

ब्लॉक का तापमान 250 से. पर रखा जाए। ब्लॉक के छिद्रों में एक तापमापक डालकर इसे नोट किया जा सकता है। यदि तापमान 250 से.से ऊपर जाता है तो कमरे में गैस भरने की सलाह दी जाती है। तथा यदि तापमान में गिरवाट आती है, तो कमरे को धीरे-धीरे गर्म किया जाना चाहिए।

पूरे पयाल में फैलने के लिए स्पान को 12 से 15 दिन लगता है तथा जब पूरा ब्लॉक सफेद हो जाए तो यह निशान है कि स्पान संचालन पूरा हो गया है।

अण्डज परिपालन के उपरांत ब्लॉक से रस्सी तथा प्लास्टिक की शीट को हटा दीजिए। नारियल की रस्सी से ब्लॉक को अनुप्रस्थ रूप में बांध दीजिए तथा इसे फसल कक्ष में लटका दीजिए। इस अवस्था से आगे कमरे की सापेक्ष आर्द्रता 85 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे दीवारों तथा कमरे की फर्श पर जल छिड़क करके समय-समय पर किया जा सकता है। यदि फर्श सीमेंट का है, तो सलाह दी जाती है कि फर्श पर पानी डालिए ताकि फर्श पर हमेश पानी रहे। यदि खंड हल्का से सूखने का लक्षण जिससे लगे तो स्प्रेयर के माध्यम से स्प्रे किया जा सकता है।

एक सप्ताह से 10 दिन के भीतर ब्लॉक की सतह पर छोटे-छोटे पिन शीर्ष दिखाई पड़ेगे तथा ये एक या दो दिन के भीतर पूरे आकार के मशरूम हो जाएंगे।

जब फल बनना शुरू होता है तो हवा की जरूरत बढ़ जाती है। अतः जब एक बार फल बनना शुरू हो जाता है तो आवश्यक है कि हर 6 से 12 घण्टो बाद कमरे के सामने और पीछे दिए गए वेंटीलेटर खोलकर ताजी हवा अंदर ली जाए। जब आवरणों की परिधि ऊपर की ओर मुड़ना शुरू हो जाती है तो फल काया (मशरूम) तोड़ने के लिए तैयार हो जाते है। ऐसा जाहिर होगा क्योंकि छोटी-छोटी सिलवटें आवरण पर दिखाई पड़ने लगती है।

मशरूम को काटने के लिए अंगूठे एवं तर्जनी से आधार पर डाल को पकड़ लीजिए तथा हल्के क्लाकवाइज मोड़ से पुआल अथवा किसी छोटे मशरूम उत्पादन को विक्षोभित किए बिना मशरूम को डाल से अलग कर लीजिए। काटने के लिए चाकू अथवा कैंची का इस्तेमाल मत करें। एक सप्ताह के बाद ब्लॉक में फिर से फल आने शुरू हो जाएंगे।

उपज

मशरूम प्रवाह में दिखाई पड़ते है। एक क्यूब से लगभग 2 से 3 प्रवाह काटे जा सकते है। प्रथम प्रवाह की उपज ज्यादा होती है तथा तत्पश्चात धीरे-धीरे कम होने लगती है तथा एक क्यूब से 1.5 किग्रा से 2 किग्रा तक के ताजे मशरूम की कुल उपज प्राप्त होती है। इसके बाद क्यूब को छोड़ दिया जाता है तथा फसल कक्ष से काफी दूर पर स्थित एक गड्ढे में पाट दिया जाता है अथवा बगीचे अथवा खेत में खाद के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

रोग एवं पीट

यदि मशरूम की देखभाल न की जाए तो अनेक रोग एवं पीट इस पर हमला कर देते हैं।

रोग

1. हरी फफूंद (ट्राइकोडर्मा विरिडे) : यह कस्तूरा कुकुरमुत्ते में सबसे अधिक सामान्य रोग है जहां क्यूबों पर हरे रंग के धब्बे दिखाई पड़ते है।

1. नियंत्रण : फॉर्मालिन घोल में कपड़े को डुबोइए (40 प्रतिशत) तथा प्रभावित क्षेत्र को पोंछ दीजिए। यदि फफूंदी आधे से अधिक क्यूब पर आक्रमण करती है तो सम्पूर्ण क्यूब को हटा दिया जाना चाहिए। इस बात की सावधानी रखी जानी चाहिए कि दूषित क्यूब को पुनर्संक्रमण से बचाने के लिए फसल कक्ष से काफी दूर स्थान पर जला दिया जाए अथवा दफना दिया जाए।

कीड़े

2. मक्खियां : देखा गया है कि स्कैरिड मक्खियां, फोरिड मक्खियां, सेसिड मक्खियां कुकुरमुत्ते तथा स्पॉन की गंध पर हमला करती हैं। वे भूसी अथवा कुकुरमुत्ते अथवा उनसे पैदा होने वाले अण्डों पर अण्डे देती हैं तथा फसल को नष्ट कर देती हैं। अण्डे माइसीलियम, मशरूम पर निर्वाह करते हैं एवं फल पैदा करने वाले शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तथा यह उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है।

नियंत्रण : फसल की अवधि में बड़ी मक्खियों के प्रवेश को रोकने के लिए दरवाजों, खिडकियों अथवा रोशनदानों पर पर्दा लगा दीजिए यदि कोई, 30 मेश नाइलोन अथवा वायर नेट का पर्दा। मशरूम गृहों में मक्खीदान अथवा मक्खियों को भगाने की दवा का इस्तेमाल करें।

3. कुटकी : ये बहुत पतले एवं रेंगने वाले छोटे-छोटे कीड़े होते हैं जो कुकुरमुत्ते के शरीर पर दिखाई देते हैं। वे हानिकारक नहीं होते है, किन्तु जब वे बड़ी संख्या में मौजूद होते है तो उत्पादक उनसे चिंतित रहता है।

नियंत्रण :घर तथा पर्यावरण को साफ सुथरा रखें।

4. शम्बूक, घोंघा : ये पीट मशरूम के पूरे भाग को खा जाते हैं जो बाद में संक्रमित हो जाते हैं तथा वैक्टीरिया फसल के गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव डालते हैं।

नियंत्रण : क्यूब से पीटों को हटाइए तथा उन्हें मार डालिए। साफ सुथरी स्थिति को बनाये रखें।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

12 डिग्रियां लेकर दुनिया के सबसे पढ़े लिखे इंसान बनने की राह पर न्यूजीलैंड के बीटन

वेलिंग्टन, एजेंसी। न्यूजीलैंड के 31 वर्षीय जेमी बीटन दुनिया के सबसे अधिक शिक्षित लोगों में शामिल होने की राह पर हैं। हार्वर्ड, येल, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड और प्रिंसटन जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से वह अब तक 12 उच्च डिग्रियां हासिल कर चुके हैं और उनकी पढ़ाई अभी जारी है। इससे पहले सबसे अधिक डिग्रियां हासिल करने वालों में बेंजामिन बी. बोल्गर के नाम 16 और माइकल निकोलसन के नाम 30 से अधिक डिग्रियां बताई जाती हैं। बीटन ने हाईस्कूल के अंतिम वर्ष में जरूरी पाठ्यक्रमों से दोगुने से अधिक विषय पढ़े और हार्वर्ड, येल व प्रिंसटन समेत 25 विश्वविद्यालयों में दाखिला मिला। 2016 में उन्होंने हार्वर्ड से मैग्ना कम लाउड सम्मान के साथ पढ़ाई पूरी की। फिलहाल वह ब्राउन यूनिवर्सिटी से डाटा साइंस में मास्टर की पढ़ाई भी कर रहे हैं। बीटन ने पढ़ाई के साथ क्रिमसन एजुकेशन की स्थापना की, जो छात्रों को प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश की तैयारी में मदद करती है। कंपनी में उनके अनुसार करीब 1,200 पूर्णकालिक कर्मचारी हैं और अब तक करीब 10 हजार छात्र इसकी सेवाएं ले चुके हैं। बीटन का कहना है कि शुरुआती पांच डिग्रियां कौशल हासिल करने के उद्देश्य से थीं, लेकिन इसके बाद वह बढ़ते गए।

सिंगापुर में अब 15 मिनट किताब पढ़ो...पैसे पाओ

सिंगापुर , एजेंसी। सिंगापुर अपने नागरिकों की लगातार स्क्रीन से चिपके रहने की बुरी आदत (डूमस्क्रॉलिंग) छुड़ाने के लिए दिन में कम से कम 15 मिनट किताब पढ़ने के एवज में पैसे दे रहा है। इस समृद्ध देश ने इसी महीने शुरू की गई इस रणनीति को गेमिफिकेशन नाम दिया है। सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से लोगों की एकाग्रता, सोच-समझकर फैसला लेने की क्षमता और कल्पनाशीलता बेहतर होगी। योजना के तहत, पढ़ने वालों को कुछ अंक मिल रहे हैं जिन्हें सेंट के बदले भुनाया जा सकता है। लोगों को 80 सेंट यानी एक डॉलर पाने के लिए एक सरकारी वेबसाइट पर रोजाना 50 रीडिंग सेशन लॉग करने होंगे। 15 मिनट के हर रीडिंग सेशन के लिए 20 वर्चुअल क्वाइन मिलेंगे और एक डॉलर के पेमेंट के लिए 1,000 क्वाइन की जरूरत होगी। नेशनल लाइब्रेरी बोर्ड की प्रमुख मेलिसा टैम ने कहा कि पढ़ने की आदतें छोटे और आसानी से पूरे किए जा सकने वाले कदमों से बनती हैं। उन्होंने कहा, हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कंटेंट, जानकारी और प्रेरणा की भरमार है। हम जानते हैं कि आदतें छोटे-छोटे, लगातार किए जाने वाले काम से बनती हैं।

खाड़ी में जहाज पर हमला

तेहरान, एजेंसी। होर्मुज जलडमरूमध्य के पास अमेरिकी जहाज पर हमला होर्मुज जलडमरूमध्य के पास अमेरिका के एक किराए के जहाज पर हमला हुआ है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह हमला ईरानी ड्रोन और मिसाइल के जरिए किया गया। इस घटना में जहाज के चालक दल के कुछ सदस्यों को मामूली चोटें आई हैं। हमले के समय जहाज पर कई अमेरिकी नागरिक भी मौजूद थे। घायल कर्मचारियों का इलाज खाड़ी देश के अस्पताल में चल रहा है। इस हमले को लेकर अभी तक अमेरिका या ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

सूडान में बड़ा हादसा: सोने की खदान ढहने से अब तक 82 लोगों की मौत, मलबे में दबे कई लोगों की तलाश जारी

नुहुद , एजेंसी। सूडान के एक दूरदराज इलाके में सोने की एक अवैध खदान ढहने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। स्थानीय अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के मुताबिक, बुधवार को बचावकर्मी सीमित उपकरणों के बीच मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे रहे। कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। बचे लोगों के मुताबिक, हादसा पश्चिम कोर्डोफान प्रांत के नुहुद शहर में स्थित अल-जारा सोने की खदान में हुआ। यह इलाका अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (आरएसएफ) के नियंत्रण में है। आरएसएफ तीन साल से अधिक समय से सूडानी सेना के खिलाफ लड़ रहा है।आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम ने बताया कि बुधवार दोपहर तक बचावकर्मियों ने 82 शव बाहर निकाले थे। उन्होंने एसोसिएटेड प्रेस से कहा, 'लेकिन दर्जनों लोग अब भी लापता हैं। यह हादसा वेस्ट कोर्डोफान प्रांत के नुहुद शहर स्थित अल-जारा सोने की खदान में हुआ। बचे लोगों के मुताबिक, खदान मंगलवार देर रात अचानक ढह गई।

'खुद कानून तोड़ने वाली ताकतें सुरक्षा परिषद में' : यूएन में सुधार पर बोले गुटेरेस- बिना सजा नियम तोड़ रहे देश

जिनेवा, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि जो वैश्विक शक्तियां खुद अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती हैं। वे ही सुरक्षा परिषद में बैठी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि 15 देशों वाले इस वैश्विक संगठन में सुधार सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए।

महासचिव गुटेरेस ने क्या कहा : महासचिव गुटेरेस ने सत्ता के पुनर्वितरण की जरूरत पर भी जोर दिया। गुटेरेस ने बुधवार को पत्रकारों से कहा, 'साफ बात यह है कि हमारे बीच भू-राजनीतिक मतभेद हैं। इन मतभेदों के बीच ऐसी ताकतें हैं जो खुद अंतरराष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करती हैं और सुरक्षा परिषद में शामिल हैं। जैसा कि हम जानते हैं, इसी वजह से सुरक्षा परिषद ठप पड़ी है। यही कारण है कि सुरक्षा परिषद में सुधार को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ऐसी सुरक्षा परिषद को स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसका स्वरूप आज की दुनिया के बजाय कई दशक पुरानी दुनिया को दर्शाता हो।'

पैरालिसिस से किया तुलना : यूएन प्रमुख ने यूएम जनरल असेंबली के 81वें सेशन के हाई-लेवल वीक की शुरुआत से पहले वर्ल्ड हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, 'और यह एक तरह का 'पैरालिसिस' (ठहराव या बेअसर होने की स्थिति) है।' गुटेरेस ने कहा कि यूएन सुरक्षा परिषद के ठप पड़ने से ऐसी स्थिति बन गई है कि दुनिया भर के हर देश को लगता है कि उन्हें अपनी मर्जी का कुछ भी करने का हक है।' क्योंकि सबसे बड़ी

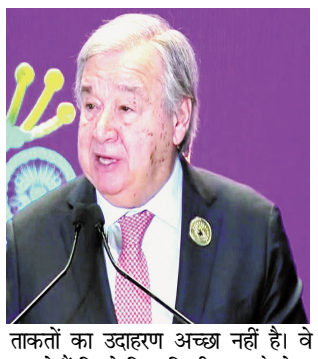

ताकतों का उदाहरण अच्छा नहीं है। वे जानते हैं कि वे बिना किसी सजा के ऐसा कर सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल खुद बेअसर हो चुकी है। 'बिना किसी सजा के बच निकलने की इसी छूट ने ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें हम देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा देश अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून और मानवाधिकार कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, और वे ऐसा बिना किसी डर या सजा के कर रहे हैं। एक बात साफ है। यह मामला असल में ताकत का है। बात यह है कि हमारी दुनिया में ताकत का बंटवारा और उसका इस्तेमाल जिस तरह से होता है, उसकी वजह से बहुपक्षीय संस्थाएं असरदार ढंग से काम नहीं कर पातीं।'

ब्रिक्स को लेकर क्या बोले : एक और सवाल के जवाब में कि क्या वह ब्रिक्स जैसे संगठनों को पावर शिफ्ट (सत्ता के बदलाव) को दिखाने के मामले में मौजूदा व्यवस्था के पूरक या विकल्प के तौर पर देखते हैं। गुटेरेस ने कहा कि आज की संस्थाएं कई दशक पहले के पावर रिलेशन (सत्ता के संबंधों) को दिखाती हैं, जिनमें से ज्यादातर दूसरे विश्व युद्ध के समय बनी थीं। लेकिन दुनिया बदल रही है, और हम नई ताकतों का उदय देख रहे हैं। और आज, अगर ग्लोबल इकॉनमी (वैश्विक अर्थव्यवस्था) को देखें, तो हर दिन ग्लोबल जीडीपी में विकसित देशों का हिस्सा थोड़ा कम हो रहा है। हर दिन ग्लोबल जीडीपी में उभरती अर्थव्यवस्थाओं का हिस्सा थोड़ा बढ़ रहा है। बता दें कि एक हफ्ते तक चलने वाली आम बहस, जिसमें दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख, विदेश मंत्री, नेता और दूत यूएन मुख्यालय में इकट्ठा होंगे। यह 22 सितंबर को शुरू होगी। इस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में मशहूर हरे पोडियम से विश्व नेताओं को संबोधित करेंगे। गुटेरेस के लिए यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का आखिरी हाई-लेवल हफ्ता होगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख के तौर पर उनका दूसरा पांच साल का कार्यकाल दिसंबर 2026 में खत्म हो रहा है।

राजनयिक के तौर पर बीते 10 वर्षों में क्या सीखा : जब उनसे पूछा गया कि दुनिया के सबसे बड़े राजनयिक के तौर पर बीते 10 वर्षों से उन्होंने क्या सबक सीखा है, तो गुटेरेस ने कहा, 'मैंने यह सबक सीखा है कि जब दुनिया तेजी से मल्टीपोलर (कई ध्रुवों वाली) होती जा रही है, तो मल्टीलेटरल (बहुपक्षीय) संस्थाओं में सुधार करना जरूरी है। ऐसा इसलिए ताकि वे संस्थाएं शांति, विकास और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के मामले में असरदार बन सकें।

पाकिस्तान में ताक पर कोर्ट का आदेश! इमरान खान की बहनों को फिर झटका, अदियाला जेल प्रशासन ने मिलने से रोका

इस्लामाबाद , एजेंसी। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात एक बार फिर नहीं हो सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद अदियाला जेल प्रशासन ने अलीमा खान, उज्मा खान और उनके वकीलों को मुलाकात की अनुमति नहीं दी। मामले को लेकर जेल प्रशासन पर न्यायालय के आदेशों की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं, जबकि परिवार ने इसे न्यायिक प्रक्रिया के उल्लंघन का मामला बताया है। वकील अवैस यूनस चौधरी ने बताया कि इमरान खान की बहनें और छह वकील उनसे मिलने के लिए जेल पहुंचे, लेकिन उन्हें एक बार फिर मिलने की इजाजत नहीं दी गई। चौधरी के हवाले से 'डॉन' ने लिखा, 'बहनें शाम 6:30 बजे के बाद भी वहां इंतजार करती रहीं, लेकिन उन्हें मुलाकात की मंजूरी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। आईएचसी ने आदेश दिया है कि इमरान खान के परिवार और वकीलों के साथ मंगलवार को और पार्टी नेताओं के साथ गुरुवार को मुलाकात कराई जाए, लेकिन कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है।' मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से अदालतें इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर रही हैं।

ईरान ने की शी जिनपिंग के शांति सिद्धांतों की तारीफ, रणनीतिक संतुलन पर दिया जोर

बीजिंग, एजेंसी। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बताए शांति के चार सिद्धांतों को बहुत ही अहम बताया। अपनी चीन यात्रा के दौरान अराघची ने वहां के सहयोगियों के साथ हुई बातचीत को भी सफल बताया। अराघची ने 'एक?स' पर पोस्ट किया, ''चीन में हमारे सहयोगियों के साथ सफल बातचीत हुई। ईरान उस रणनीतिक साझेदारी को अहमियत देता है जो हमने समय के साथ बनाई है। आज लिए गए फैसले इस क्षेत्र में भविष्य के रणनीतिक संतुलन को तय करेंगे और इनके दूरगामी असर होंगे। राष्ट्रपति शी की ओर से शांति के लिए बताए गए चार सिद्धांत बहुत अहम हैं।'' इससे पहले चीन के विदेश मंत्री और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना (सीपीसी) की सेंट्रल कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो सदस्य वांग यी ने बुधवार को अराघची से मुलाकात की। चीनी विदेश मंत्रालय के हवाले से ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर ने बताया कि चीन की राजधानी में अराघची से मुलाकात के दौरान वांग ने कहा, 'ईरान के साथ बातचीत और सहयोग को मजबूत करने और ईरान के जायज अधिकारों और हितों की रक्षा करने को चीन तैयार है।' चीन के विदेश मंत्री ने ईरानी समकक्ष के साथ बैठक में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलने का भी आग्रह किया। रिपोर्ट के अनुसार, चीनी विदेश मंत्रालय ने बताया कि बीजिंग में बुधवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अपने ईरानी समकक्ष से कहा कि चीन चाहता है कि ईरान और

अमेरिका को आपसी चिंता के मुद्दों पर ठोस बातचीत करने के लिए तैयार हों। वांग ने कहा, 'हम सभी पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे होर्मुज स्ट्रेट को जल्द से जल्द फिर से खोलने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।' उन्होंने कहा कि चीन नहीं चाहता कि क्षेत्रीय तनाव बढ़े और यमन तथा लाल सागर तक फैल जाए।

अराघची ने एक्स पर दी जानकारी : अराघची ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'चीन में हमारे सहयोगियों के साथ सफल बातचीत हुई। ईरान उस रणनीतिक साझेदारी को अहमियत देता है जो हमने समय के साथ बनाई है। आज लिए गए फैसले इस क्षेत्र में भविष्य के रणनीतिक संतुलन को तय करेंगे और इनके दूरगामी असर होंगे। राष्ट्रपति शी की ओर से शांति के लिए बताए गए चार सिद्धांत बहुत अहम हैं।चीनी विदेश मंत्रालय के हवाले से ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर ने बताया कि चीन की राजधानी में अराघची से मुलाकात के दौरान वांग ने कहा, 'ईरान के साथ बातचीत और सहयोग को मजबूत करने और ईरान के जायज अधिकारों और हितों की रक्षा करने को चीन तैयार है।

गाजा में इजरायली बमबारी में क्षतिग्रस्त बहुमंजिला इमारत गिरी, 11 बच्चों समेत 21 लोगों की मौत

गाजा , एजेंसी। पश्चिमी गाजा शहर में एक रिहायशी इमारत गिरने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। मृतकों में 11 बच्चे और 6 महिलाएं शामिल हैं। इस हादसे में 25 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता महमूद बासल ने बताया कि 'अल-सादा' नाम की छह मंजिला इमारत बुधवार तड़के ढह गई। यह इमारत पहले इजरायली बमबारी में क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। यह इमारत निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) के मुख्यालय के पास स्थित थी। इस इमारत में लगभग 100 विस्थापित लोग रह रहे थे। सि?न्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, बासल ने कहा कि बचाव टीमों ने 16 घंटे तक चले अभियान के दौरान 45 लोगों को सुरक्षित निकाला और 21 शव बरामद किए। उन्होंने बताया कि 35 अन्य लोग खुद ही निकलने में सफल रहे। इमारत के मलबे के बाहर दर्जनों शोकाकुल परिजन इकट्ठा हुए। कई लोग अपने हाथों से ही मलबा हटाकर अपने प्रियजनों को खोजने की कोशिश करते दिखाई दिए। 54 वर्षीय लुआय अल-अजला ने इस हादसे में अपने परिवार के लगभग 10 लोगों को खो दिया। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि बचाव कार्यों के लिए जरूरी भारी मशीनों और उपकरणों को लाने पर इजरायल की पाबंदियों के कारण राहत कार्य प्रभावित हो रहे हैं। गाजा में हमास की ओर से संचालित मीडिया कार्यालय ने एक बयान में कहा कि पूरे गाजा पट्टी में 8,500 से अधिक लापता लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बयान के अनुसार, भारी मशीनरी और बचाव उपकरणों की कमी के कारण उन्हें निकालना मुश्किल हो रहा है। कार्यालय ने हजारों क्षतिग्रस्त इमारतों को टाइम बम जैसा खतरा बताया। महमूद बासल ने चेतावनी दी कि सर्दियों के करीब आने के साथ 2,000 से अधिक रिहायशी इमारतों के गिरने का खतरा बना हुआ है। उन्होंने 'बोर्ड ऑफ पीस' और युद्धविराम की गारंटी देने वाले देशों से अपील की कि बचाव उपकरणों को गाजा में आने की अनुमति दिलाई जाए।ऐसा न होने पर 'कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है।

तकनीक: रोबोट ही बना रहे रोबोट, हर 10 मिनट में एक हो रहा तैयार; चीन में दुनिया की पहली फैक्ट्री होने का दावा

बीजिंग, एजेंसी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के कारण नौकरियां कम होने के मुद्दे पर जारी विमर्श के बीच चीन से प्रौद्योगिक विकास की नई तस्वीर आई है। यहां रोबोट ही दूसरे रोबोट के निर्माण में मदद कर रहे हैं। यूबीटेक रोबोटिक्स ने यहां एक नई ह्यूमनॉइड रोबोट फैक्ट्री खोली है। इसकी उत्पादन क्षमता 10 हजार प्रति वर्ष है। दावा है कि इतनी बड़ी उत्पादन क्षमता वाली यह दुनिया की पहली फैक्ट्री है।

गुआंग्शी जुआंग स्वायत्त क्षेत्र के लियूझोउ में स्थित यह फैक्ट्री विनिर्माण प्रक्रिया के कुछ हिस्सों को संभालने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करती है। यह हर 10 मिनट में एक इंडस्ट्रियल ह्यूमनॉइड रोबोट बना सकती है। 14,000 वर्ग मीटर में फैली यह फैक्ट्री 13.8 मीटर ऊंची है और मुख्य रूप से यूबीटेक की वाकर एस

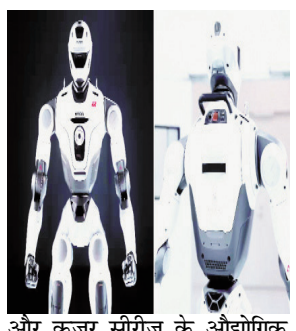

और क्रूजर सीरीज के औद्योगिक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाती है। इसे यूबीटेक और सीमेंस डिजिटल इंडस्ट्रीज सॉफ्टवेयर ने मिलकर बनाया है।

हर रोबोट का अलग नंबर, अलग काम : फैक्ट्री को एक डिजिटल प्रणाली संचालित करती है जिसे यूबीटेक अपना स्मार्ट ब्रेन कहती है। कंपनी के अनुसार, यह प्रणाली फैक्ट्री के संचालन में मदद करती है... क्या बनाया जाना है, इसका निर्णय लेने से लेकर पुर्जों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने और तैयार रोबोटों की गुणवत्ता जांचने तक। प्रत्येक रोबोट को अपना अलग सीरियल नंबर भी दिया जाता है।

क्या काम करते हैं रोबोट : यूबीटेक के अनुसार, उसके क्रूजर वाई 1 व क्रूजर एस2 रोबोट सामग्री उतारने, उन्हें व्यवस्थित ढंग से रखने, लोड करने और उत्पादन क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने जैसे काम करते हैं।

इंसानी निगरानी न के बराबर : कंपनी का कहना है कि एक ही उत्पादन लाइन पर रोबोट के अलग-अलग मॉडल बनाए जा सकते हैं। पूरी तरह अलग-अलग असेंबली सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती। स्मार्ट और अन्य प्रकार की मशीनें आपस में मिलकर काम करती हैं और इस प्रक्रिया में इंसानों की निगरानी बहुत कम या लगभग न के बराबर होती है।

चार घंटे का परीक्षण : फैक्ट्री से किसी ह्यूमनॉइड रोबोट के बाहर निकलने से पहले उसकी विस्तृत जांच की जाती है। इसमें करीब चार घंटे का समय लगता है। इसके बाद उसकी 360 डिग्री विजुअल इंस्पेक्शन की जाती है। इसमें हर कोण से रोबोट की बाहरी स्थिति और बनावट की जांच की जाती है।

तेजी से बढ़ रहा उत्पादन : चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स (एनबीएस) के अनुसार, देश में जुलाई में 98,677 औद्योगिक रोबोट बनाए गए जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 30.2 प्रतिशत अधिक है। इस साल के पहले सात महीनों में औद्योगिक रोबोटों का उत्पादन 6,35,056 इकाइयों तक पहुंच गया, जो साल-दर-साल 28.5 प्रतिशत की वृद्धि है।

अमेरिकी केंद्रीय बैंक का बड़ा फैसला: राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव को दरकिनार कर फेड ने बढ़ाई ब्याज दरें

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में जिद्दी बनी महंगाई पर लगाम कसने के लिए केंद्रीय बैंक 'फेडरल रिजर्व' ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। व्हाइट हाउस के लगातार दबाव को दरकिनार करते हुए फेडरल रिजर्व ने बुधवार को बेंचमार्क ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। वर्ष 2023 के बाद से यह पहला मौका है जब अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में इजाफा किया है। इस फैसले से न केवल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कम ब्याज दरों की मांग को झटका लगा है, बल्कि इसका असर वैश्विक बाजारों पर भी देखने को मिल सकता है।

महंगाई पर लगाम लगाने के लिए उठाया सख्त कदम : फेडरल रिजर्व ने मुख्य ब्याज दर (बेंचमार्क रेट) में 25 बेसिस प्वाइंट (0.25 फीसदी) की बढ़ोतरी की है। इस फैसले के बाद अमरीका में मुख्य ब्याज दर बढ़कर लगभग 3.9 फीसदी हो गई है। बैंक के इस कदम का सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, जिससे समय के साथ होम लोन, ऑटो लोन और क्रेडिट कार्ड पर ब्याज दरें महंगी हो जाएंगी। त्रैमासिक अनुमानों को जारी करते हुए फेड की दर-निर्धारण समिति (एफओएमसी) ने संकेत दिया है कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए इस साल के अंत तक ब्याज दरों को एक बार फिर बढ़ाकर 4.1 फीसदी तक किया जा सकता है।

केंद्रीय बैंक ने अपने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया, 'आज की नीतिगत कार्रवाई मुद्रास्फीति (महंगाई) को केंद्रीय बैंक के दो प्रतिशत के लक्ष्य पर समयबद्ध तरीके से वापस लाने में मदद करेगी।'

चुनाव से ठीक पहले आम जनता पर दोहरा बोझ : फेड का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी जनता पहले से ही खाद्य पदार्थों, पेट्रोल-डीजल और आवास की बढ़ती कीमतों से जूझ रही है। अमेरिका में महज सात हफ्ते बाद मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं, और ऐसे में बढ़ती महंगाई चुनावी अभियानों का सबसे मुख्य मुद्दा बन चुका है। ब्याज दरों के बढ़ने से आम उपभोक्ताओं के लिए कर्ज लेना और महंगा हो जाएगा।

चेयरपर्सन केविन वॉश का क्या रुख : यह फैसला फेडरल रिजर्व के नए चेयरपर्सन केविन वॉश के रुख में आए एक बड़े मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नियुक्त किए गए केविन वॉश ने इसी साल मई में फेड अध्यक्ष का पद संभाला था। पिछले साल जब ट्रंप इस पद के लिए उनके नाम पर विचार कर रहे थे, तब वॉश ने कई बार संकेत दिए थे कि फेड ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। उन्होंने कम ब्याज दरों की राष्ट्रपति ट्रंप की मांग का समर्थन भी किया था। हालांकि, पद संभालने और लगातार ऊंची बनी महंगाई के आंकड़ों के बीच वॉश ने राजनीतिक दबाव के बजाय केंद्रीय बैंक की नीतिगत स्वायत्तता और महंगाई नियंत्रण को प्राथमिकता दी है।

यूरोपीय संघ: 13 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर लगे रोक, सख्त नियमों का रखा प्रस्ताव

ब्रुसेल्स , एजेंसी। यूरोपीय संघ (ईयू) 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। 27 सदस्यीय देशों के संघ ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन बुधवार को स्ट्रासबर्ग में स्टेट ऑफ द यूरोपियन यूनियन पर अपने सालाना भाषण के दौरान 13 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम और चैटबॉट इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव रखा। इससे बड़ी उम्र के किशोरों के लिए भी कड़े नियम प्रस्तावित किए हैं।

लेयेन ने कहा कि कई लोग बड़ी टेक कंपनियों की ताकत को बहुत अधिक मानते हुए उसे कम करना नामुमकिन मानते हैं, लेकिन हम इससे सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि कि बच्चों को लत लगाने वाले फीचर्स, अत्यधिक उग्र सामग्री, लड़कियों की फोटो का इस्तेमाल, एआई से बनाई गई यौन तस्वीरों के खतरे से बचाया जाना चाहिए। उन्होंने इस तरह के प्रतिबंधों का चरणबद्ध खाका पेश किया।

नियमों पर आज साफ हो सकती है स्थिति : उन्होंने कहा कि 13 से 15 साल के बच्चों को समय-सीमा के साथ अभिभावकों की देखरेख वाले मिनी अकाउंट्स दिए जाएंगे, जबकि 15 से 18 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को सुरक्षित डिजाइन उपलब्ध कराना होगा। इस प्रस्ताव को लेकर अधिक जानकारी गुरुवार को आने की उम्मीद है।

एआई पर कनाडा-ब्रिटेन का लेगा सहयोग : यूरोपीय संसद के सबसे बड़े समूह के प्रमुख मैनफ्रेड वेबर ने उपयोगकर्ताओं को सोशल मीडिया एल्गोरिदम बंद करने का विकल्प देने का भी प्रस्ताव रखा। लेयेन ने एआई पर कनाडा और ब्रिटेन के साथ सहयोग से मिलकर काम करने की बात कही, जिसमें मॉडल मूल्यांकन, सत्यापन, शुरुआती चेतावनी और एआई सुरक्षा शामिल हैं। ईयू ने यह कदम स्पेन, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका की बच्चों के हित में सोशल मीडिया कंपनियों की नकले कसने की पहलों के बाद उठाया है। प्रस्ताव के मुताबिक ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन समेत सभी 27 देशों में 13 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों को केवल माता-पिता की निगरानी और नियंत्रण वाले मिनी अकाउंट इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी।

ट्रंप प्रशासन का फैसला: गोरों के खिलाफ भेदभाव के आरोपों पर होगा एक्शन, दक्षिण अफ्रीकी अफसरों पर लगाया बैन

केप टाउन, एजेंसी। ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को एक नई घोषणा की। प्रशासन का कहना है कि वे उन अधिकारियों के यात्रा पर प्रतिबंध लगाएगा, जिनके बारे में यह दावा है कि वे दक्षिण अफ्रीका में गोरों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ भेदभाव के लिए जिम्मेदार हैं।

अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो ने क्या कहा : अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मंगलवार को कहा कि वह उन विदेशी नागरिकों के अमेरिकी वीजा रद्द कर देंगे या वीजा आवेदनों को अस्वीकार कर देंगे, जो दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक जातीय और नस्लीय समूहों के खिलाफ बिना मुआवजे के भूमि अधिग्रहण, नस्ल-आधारित भेदभाव और हिंसा भड़काने की अनुमति देने वाले कानूनों और नीतियों को लागू करने या उनका पालन करने के लिए जिम्मेदार या इसमें शामिल पाए जाते हैं। रुबियो ने एक बयान में कहा, 'अमेरिका इस तरह के व्यवहार को बेरोकटोक नहीं चलने देगा। ये कार्रवाइयां सीधे तौर पर शांति, आर्थिक स्थिरता और कानून के शासन को कमजोर करती हैं। ये अमेरिका की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों के विपरीत हैं।'

दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने क्या कहा : दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने श्वेत लोगों के खिलाफ भेदभाव के अमेरिकी आरोपों को

दृढ़ता से खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पिछले साल सत्ता में लौटने के बाद से प्रशासन की ओर से किए गए दावे निराधार और गलत सूचना का परिणाम हैं।

क्या अधिकारियों की पहचान हुई है : रुबियो ने उन अधिकारियों की पहचान नहीं की जिन्हें यात्रा प्रतिबंधों के तहत निशाना बनाया जाएगा। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक श्वेतों के एक लॉबी समूह ने पहले अमेरिका से अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था, जो दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा की पार्टी है और दक्षिण अफ्रीका की संसद में सबसे बड़ी पार्टी है।

दक्षिण अफ्रीका ने क्या दावा किया : यह ट्रंप प्रशासन का दक्षिण अफ्रीका पर प्रतिबंध लगाने का ताजा कदम है। दक्षिण अफ्रीका का दावा है कि वहां की अश्वेत-नेतृत्व वाली सरकार गोरों, और खासकर अफ्रीकनर समुदाय के साथ भेदभाव कर रही है। अफ्रीकानर मुख्य रूप से डच और फ्रांसीसी औपनिवेशिक प्रवासियों के वंशज हैं, जो पहली बार 17वीं शताब्दी में दक्षिण अफ्रीका आए थे। वे दक्षिण अफ्रीका की पिछली नस्लीय भेदभाव प्रणाली के केंद्र में थे। दक्षिण अफ्रीका की 62 मिलियन आबादी में लगभग 45 लाख श्वेत लोग हैं, जिनमें ब्रिटिश या अन्य मूल के श्वेत लोग भी शामिल हैं। अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका में गोरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोधी रुख के सबूत के तौर पर कुछ विवादित कानूनों और नीतियों का हवाला दिया है। इनमें दक्षिण अफ्रीका का वह विवादित कानून शामिल है, जो कुछ खास हालात में बिना किसी मुआवजे के इस्तेमाल न हो रही निजी जमीन को जब्त करने की इजाजत देता है। इसके साथ ही, अश्वेतों और अन्य लोगों के लिए अवसर बढ़ाने वाली 'अफरमेटिव एक्शन' (सकारात्मक कार्रवाई) नीतियां और गोरे किसानों के खिलाफ हिंसा की कुछ घटनाएं भी इसमें शामिल हैं।

ट्रंप प्रशासन ने दक्षिण अफ्रीका के उस कदम की भी कड़ी आलोचना की है, जिसमें उसने संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत में एक बेहद संवेदनशील मामले के तहत अमेरिकी सहयोगी इस्राइल पर गाजा में फिलिस्तीनियों के नरसंहार का आरोप लगाया है।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशक: सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

आश्वासन के बाद किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म, मुख्य सचिव स्तर की होगी वार्ता

नई दिल्ली (एजेंसी)। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के कार्यालय पर एक सप्ताह से चल रहा किसान संघर्ष मोर्चा का धरना गुरुवार को आश्वासन के बाद खत्म हो गया। 5 अक्टूबर तक लखनऊ में मुख्य सचिव स्तर की वार्ता होगी। किसान 10 फीसदी आबादी भूखंड की मांग पर अड़े हैं और उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर 6 अक्टूबर से फिर धरना शुरू करने की चेतावनी दी है। किसान संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के सीईओ, जिलाधिकारी एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त के बीच करीब तीन घंटे बातचीत हुई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसान नेता डॉ. रुपेश वर्मा ने बताया कि 21 सितंबर तक प्राधिकरण और किसान नेता 10 फीसदी आबादी भूखंड समेत अन्य मुद्दों पर जरुरी तैयारी पूरी करेंगे। इसके बाद 5 अक्टूबर तक लखनऊ में मुख्य सचिव और औद्योगिक विकास आयुक्त स्तर पर वार्ता होगी। उन्होंने कहा कि वार्ता सकारात्मक रहने पर मुख्यमंत्री स्तर पर अंतिम वार्ता कराने का प्रस्ताव है। किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर 6 अक्टूबर से फिर आंदोलन किया जाएगा।

सभी दवा दुकानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

नई दिल्ली (एजेंसी)। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल स्टोर पर बिना पर्चे के दवाओं की बिक्री रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 में संशोधन का मसौदा जारी किया गया है। प्रस्ताव के तहत मेडिकल स्टोर पर होने वाली दवा बिक्री की निगरानी कैमरों के माध्यम से की जा सकेगी। खास तौर पर अनुसूची एच, एच1 और एक्स श्रेणी की दवाओं की बिक्री पर नजर रखी जाएगी। इन दवाओं को वैध चिकित्सकीय पर्चे के आधार पर ही बेचा जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मसौदे पर आम लोगों और संबंधित पक्षों से आपत्तियां व सुझाव मांगे हैं। प्रस्ताव लागू होने के बाद दवा दुकानों पर कैमरों के जरिए बिक्री प्रक्रिया की निगरानी बढ़ने की उम्मीद है।

अधिकारी की मेज पर कुत्ते छोड़ने वाले शिवसेना (यूबीटी) कार्यकर्ता पर मामला दर्ज

नासिक (एजेंसी)। महाराष्ट्र के नासिक जिले में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक के विरोध में नगरपालिका के एक अधिकारी के कक्ष में जबरन घुसकर उनकी मेज पर बोरियों से निकालकर दो कुत्ते छोड़ने वाले शिवसेना (यूबीटी) के कार्यकर्ता और अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिवसेना (यूबीटी) नेता आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वह इस घटना के दौरान कुत्तों के साथ किए गए व्यवहार से आहत हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि नगर निकाय के अधिकारियों की निष्क्रियता को उजागर करने के लिहाज से वे सही थे, फिर भी ऐसे कृत्यों को दोहराया नहीं जाना चाहिए। निफाड थाने के अधिकारी ने बताया कि एक लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालने के आरोप में विक्रम रंधावे और उनके सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता के संबंध में भी मामला दर्ज किया है, क्योंकि प्रदर्शनकारी कुत्तों को बोरियों में लेकर आए थे।

अमृतसर में ड्यूटी पर तैनात एएसआई की हत्या, आतंकी संगठन ने ली जिम्मेदारी

अमृतसर(एजेंसी)। पंजाब के अमृतसर में बीती रात ड्यूटी पर तैनात असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (एएसआई) हरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या की गई। हरजीत बाइक पर गश्त कर रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया। गंभीर रूप से घायल हरजीत को अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर हमलावरों की पहचान और घटना के पीछे की मंशा का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। यह वारदात रात करीब 2:30 बजे हुई, जब एएसआई सिंह दाना मंडी के पास बाइक पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी बाइक पर आए दो अज्ञात हमलावरों ने दाना मंडी के गेट नंबर दो के बाहर उनकी गर्दन में गोली मार दी। फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल हरजीत को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से हमलावरों का पता लगाने में जुटी है। हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान (टीटीएच) नाम के आतंकी संगठन ने लेने का दावा किया है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। गौरतलब है कि अमृतसर में पहले भी पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया जा चुका है। कुछ महीने पहले मजीठा क्षेत्र में एएसआई जोग सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और 11 सितंबर को अजनाला इलाके में एएसआई जसवंत सिंह पर हमला हुआ था, जिसमें वह बाल-बाल बचे थे। उन हमलों की जिम्मेदारी भी टीटीएच ने ही ली थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एएसआई हरजीत सिंह की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि सिंह की बहादुरी और ड्यूटी के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा।

तमिलनाडु के सीएम विजय बनेंगे लाखों बच्चों के 'मामा', हर नवजात को देंगे एक ग्राम सोने की अंगूठी

चेन्नई , एजेंसी।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों को एक ग्राम सोने की अंगूठी देने की योजना शुरू करने जा रहे हैं। 'थाइमामन थांगा मोतीराम' यानी 'मामा की ओर से सोने की अंगूठी' नाम की इस योजना की औपचारिक शुरुआत 28 सितंबर को होगी। योजना के तहत 22 जून 2026 के बाद सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले पात्र बच्चों को अंगूठी दी जाएगी।
इस योजना की एक प्रमुख शर्त यह है कि बच्चे का जन्म तमिलनाडु के सरकारी अस्पताल में हुआ हो और लाभार्थी परिवार राज्य का स्थायी निवासी हो। सरकार के मुताबिक, योजना का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देना और लोगों का सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा बढ़ाना है।
तमिलनाडु सरकार के अनुसार राज्य में हर साल करीब 7.8 लाख बच्चों का जन्म होता है। इनमें लगभग 4.2 लाख यानी करीब 53 प्रतिशत बच्चों का जन्म सरकारी अस्पतालों में होता है। पहले चरण के लिए करीब 1.28 लाख सोने की अंगूठियां खरीदी जा चुकी हैं। प्रत्येक अंगूठी पर एक विशिष्ट क्रमांक दर्ज होगा।
यह योजना तमिल संस्कृति में प्रचलित उस परंपरा से प्रेरित है, जिसमें बच्चे के जन्म पर मामा या ननिहाल की ओर से उपहार दिया जाता है। मुख्यमंत्री विजय ने चुनाव के दौरान भी इस योजना का वादा किया था। योजना की घोषणा ऐसे समय हुई है, जब राज्य में दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि, इन उपचुनाव क्षेत्रों में योजना लागू करने के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति से जुड़े प्रावधान भी सामने आए हैं।
सुबोध/18 -09-2026(चेन्नई) तमिलनाडु के सीएम विजय बनेंगे लाखों बच्चों के 'मामा', हर नवजात को देंगे एक ग्राम सोने की अंगूठी
चेन्नई (ईएमएस)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों को एक ग्राम सोने की अंगूठी देने की योजना शुरू करने जा रहे हैं। 'थाइमामन थांगा मोतीराम' यानी 'मामा की ओर से सोने की अंगूठी' नाम की इस योजना की औपचारिक शुरुआत 28 सितंबर को होगी। योजना के तहत 22 जून 2026 के बाद सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले पात्र बच्चों को अंगूठी दी जाएगी।
इस योजना की एक प्रमुख शर्त यह है कि बच्चे का जन्म तमिलनाडु के सरकारी अस्पताल में हुआ हो और लाभार्थी परिवार राज्य का स्थायी निवासी हो। सरकार के मुताबिक, योजना का उद्देश्य सरकारी अस्पतालों में प्रसव को बढ़ावा देना और लोगों का सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर भरोसा बढ़ाना है।
तमिलनाडु सरकार के अनुसार राज्य में हर साल करीब 7.8 लाख बच्चों का जन्म होता है। इनमें लगभग 4.2 लाख यानी करीब 53 प्रतिशत बच्चों का जन्म सरकारी अस्पतालों में होता है। पहले चरण के लिए करीब 1.28 लाख सोने की अंगूठियां खरीदी जा चुकी हैं। प्रत्येक अंगूठी पर एक विशिष्ट क्रमांक दर्ज होगा।
यह योजना तमिल संस्कृति में प्रचलित उस परंपरा से प्रेरित है, जिसमें बच्चे के जन्म पर मामा या ननिहाल की ओर से उपहार दिया जाता है। मुख्यमंत्री विजय ने चुनाव के दौरान भी इस योजना का वादा किया था। योजना की घोषणा ऐसे समय हुई है, जब राज्य में दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि, इन उपचुनाव क्षेत्रों में योजना लागू करने के लिए निर्वाचन आयोग की अनुमति से जुड़े प्रावधान भी सामने आए हैं।

ऑस्ट्रेलिया के वीजा नियमों में बदलाव, छात्र साथ नहीं ले जा सकते पार्टनर और बच्चे , भारतीयों पर पड़ेगा असर

नई दिल्ली (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने देश के अस्थायी वीजा नियमों में बड़े और कड़े बदलावों का ऐलान किया है, जिसका सीधा असर अब अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर पड़ेगा। नए नियमों के तहत अब अधिकांश विदेशी छात्र अपने पार्टनर या बच्चों को डिपेंडेंट वीजा पर अपने साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं ला सकते है। इस फैसले से सबसे बड़ा झटका भारतीय छात्रों को लगने की आशंका है, क्योंकि अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया उच्च शिक्षा के लिए युवाओं के बीच दूसरा सबसे पसंदीदा देश है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों में बिजनेस, आईटी, इंजीनियरिंग और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों की पढ़ाई करने वाले छात्रों की संख्या 1.38 लाख से अधिक है, जो वहां के कुल विदेशी छात्रों का करीब 16 प्रतिशत हिस्सा है। ऑस्ट्रेलियाई गृह मंत्री टोनी बर्क द्वारा घोषित इन सख्त उपायों का मुख्य उद्देश्य देश में अस्थायी प्रवासन (माइग्रेशन) को नियंत्रित करना और वर्ष 2027-28 तक नेट ओवरसीज माइग्रेशन को घटाकर 225,000 के लक्ष्य तक लाना है। ऑस्ट्रेलिया सरकार का कदम अंतरराष्ट्रीय छात्रों, वर्किंग-हॉलिडे वीजा धारकों और वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी देश में अवैध रूप से जमे रहने वाले लोगों पर शिकंजा कसने के लिए उठाया गया है। हालांकि, इस नीति में कुछ विशेष अपवाद भी रखे गए हैं। नई व्यवस्था के तहत पैसिफिक और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के छात्रों को परिवार के लिए वीजा की सुविधा मिलती रहेगी, और पीएचडी (पीएचडी) जैसे उच्च शोध कार्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्र भी अपने परिवार को साथ रख सकते है।

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चार संदिग्ध बांग्लादेशी को पुलिस ने पकड़ा

-महिलाओं के कपड़े पहनकर महीनों से होटल में रहे थे, नहीं हुआ किसी को शक

कोलकाता, एजेंसी।
पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चार संदिग्ध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि ये चारों पिछले तीन महीनों से एक होटल में रह रहे थे। वे पहचान छिपाने के लिए साड़ी, नाइटी और सलवार-सूट पहनकर होटल से बाहर निकलते थे। मामला 13 सितंबर को सामने आया। जब रघुनाथपुर में पुलिस ने साड़ी पहने एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा। पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की। उसने अपना नाम तौहीद मंडल बताया।
पुलिस ने बताया कि तौहीद बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि वह कुछ अन्य लोगों के साथ भारत आया था। वे 1 सितंबर को नदिया जिले के अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र से कथित तौर पर भारत में दाखिल हुए थे। मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने पुरुलिया टाउन थाना क्षेत्र के एक होटल पर छापा मारा। यहां से तीन अन्य संदिग्धों को हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान जाहिद इमन, सुमन शेख और शांत हुसैन के रूप में हुई है। इनके पते बांग्लादेश के राजबाड़ी और कुश्टिया जिलों के बताए गए हैं।
जांच में सामने आया कि चारों जिस होटल में रह रहे थे, वहां कमरा मनी सरकार नाम की महिला के आधार कार्ड से बुक किया गया था। मनी सरकार उत्तर 24 परगना की रहने वाली बताई गई हैं। होटल मालिक ने बताया कि कमरे के लिए सिर्फ एक व्यक्ति का आधार कार्ड लिया गया था। इसके बावजूद कमरे में चार लोग रह रहे थे।
रिपोर्ट के मुताबिक होटल मालिक ने पुलिस को बताया कि उन्हें इन लोगों के बांग्लादेशी होने की जानकारी नहीं थी। वे कभी दो दिन होटल में रुकते थे और फिर चले जाते थे। होटल के सुरक्षा गार्ड ने बताया कि उन्हें कभी शक नहीं हुआ। ये लोग साड़ी, नाइटी और सलवार-सूट जैसे कपड़े पहनते थे। वे टोटो से बाहर जाते थे और फिर होटल लौट आते थे। होटल कर्मचारी ने बताया कि वह उन्हें अक्सर सीढ़ियों से ऊपर जाते देखती थीं। उनके कपड़े और हावभाव महिलाओं जैसे लगते थे। इसलिए कभी शक नहीं हुआ। चारों संदिग्धों को डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि वे सीमा पार करके पुरुलिया तक कैसे पहुंचे। पुलिस जांच कर रही है कि वे इतने लंबे समय तक होटल में कैसे रहे। इसके अलावा पुलिस उनके पुरुलिया आने की वजह और स्थानीय संपर्कों का पता लगा रही है। फिलहाल सभी संदिग्ध पुलिस की हिरासत में हैं।

राहुल गांधी बोले- अब तो पार्टियां ही चुराने लगी भाजपा

टीएमसी का नाम और चुनाव चिन्ह फ्रीज राजनीति

नई दिल्ली, एजेंसी।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नाम और चुनाव चिन्ह को चुनाव आयोग द्वारा फ्रीज किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने इस घटना को वोट चोरी, सरकार चोरी और अब पार्टी चोरी का प्रतीक बताया और इसे भारत के लोकतांत्रिक पतन का संकेत करार दिया। राहुल गांधी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह एक ऐसा पैटर्न है जो बार-बार दोहराया जा रहा है पहले शिवसेना, फिर एनसीपी और अब तृणमूल कांग्रेस। उन्होंने आरोप लगाया कि हर बार भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर एक पार्टी को तोड़ते हैं और फिर उसका चुनाव चिन्ह छीन लिया जाता है। गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि जब पूरी की पूरी पार्टी ही चोरी हो सकती है, तो करोड़ों भारतीयों के वोट चोरी होना कोई हैरानी की बात नहीं है। उनके अनुसार, वोट चोरी। सरकार चोरी। अब पार्टी चोरी। ये हमारे लोकतांत्रिक पतन के

प्रतीक बन गए हैं।
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी जनादेश की रक्षा करना है, लेकिन इसके बजाय, वह उन ताकतों की मदद कर रहा है जो जनता के फैसले को ही पलट देते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह लड़ाई सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है, बल्कि यह हर राजनीतिक दल और हर मतदाता की लड़ाई है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहता है। दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों के लिए पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को फिलहाल फ्रीज करने का आदेश दिया है। इसका अर्थ यह है कि जब तक आयोग इस मामले में कोई अंतिम फैसला नहीं ले लेता, तब तक न तो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट और न ही ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाला गुट किसी भी चुनाव के लिए टीएमसी के नाम और पार्टी के चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कर पाएगा। यह विवाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में हार के बाद अप्रैल में टीएमसी के दो गुटों में बंटने से शुरू हुआ था। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने को लेकर यह विवाद बढ़ा और बाद में टीएमसी के 80 में से लगभग 58 विधायक ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में बागी गुट का हिस्सा बन गए। दलबदल विरोधी कानून के तहत यह संख्या दो-तिहाई बहुमत के आंकड़े से अधिक थी। इस विभाजन के बाद, दोनों गुट टीएमसी के नाम और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपना दावा कर रहे थे। फिलहाल, आयोग ने स्थिति को देखते हुए पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को फ्रीज कर दिया है।

स्वतंत्र भारद्वाज तिहाड़ जेल से रिहा, मोदी-योगी और राजनीति पर दिया बड़ा बयान

नई दिल्ली(एजेंसी)। जंतर-मंतर पर एक छात्र कार्यकर्ता के पिता के साथ मारपीट के मामले में जेल में बंद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्वतंत्र भारद्वाज को तिहाड़ जेल से तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया। दिल्ली की अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 6 अक्टूबर तक टाल दी है, और कोर्ट उनके अंतरिम जमानत के दौरान के आचरण का आकलन करेगा। अदालत ने उनके सोशल मीडिया पर मामले से जुड़े किसी भी प्रकार के पोस्ट या चर्चा करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया है। रिहाई के बाद उनका एक निजी इंटरव्यू तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके लिए किसी भी राजनीतिक दल या नेता से बढ़कर केवल समाज सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि आज के समय में देश की मुख्य मांग आर्थिक आरक्षण को लागू करना और यूजीसी के नियमों को वापस लेना है। उन्होंने किसी भी पार्टी का पक्ष न लेकर कहा कि जो नेतृत्व आम जनता को मुसीबत में डाले, वह सही नहीं है, असली नेता वहीं है जो खुद लाठी खाए और गिरफ्तारी देने के लिए तैयार रहे।

स्मार्ट स्कूल से पहले बुनियादी सुविधाएं जरूरी: मायावती

यूपीआई शुल्क से आमजन की जेब पर बढ़ेगा बोझ

लखनऊ, एजेंसी।
बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 15 अक्टूबर से लागू होने वाली नई यूपीआई शुल्क व्यवस्था को लेकर सरकार पर तीखा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यूपीआई डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के बाद अब इस पर शुल्क लगाने की व्यवस्था से आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। मायावती ने उत्तर प्रदेश में 14,429 परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए मंजूर करीब 300 करोड़ रुपये की योजना पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि डिजिटल शिक्षा से पहले स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए।
मायावती ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूपीआई डिजिटल लेनदेन को पहले खूब बढ़ावा देने के बाद अब सरकार द्वारा उस लेनदेन पर शुल्क वसूलने की नई व्यवस्था लोगों की नजर में प्रथमदृष्टया मुनाफाखोरी के पूंजीवादी रवैये के तहत जनता से दोनों हाथों से टैक्स वसूली है, जिससे जनता में बेचैनी व आक्रोश स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि वैसे तो जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने की इस व्यवस्था को कर मानने को तैयार नहीं है, लेकिन 15 अक्टूबर से लागू होने वाली इस व्यवस्था को चाहे जो भी नाम दिया जाये, जेब तो अन्ततः आम जनता की ही कटेगी, उसका ही खर्च बढ़ेगा। मायावती ने आगे कहा कि देश की बहुसंख्यक जनता अपार गरीबी व जबरदस्त महंगाई आदि की मार से त्रस्त है और उनके बच्चे अशिक्षा, बेरोजगारी व अव्यवस्था आदि से पीड़ित हैं; ऐसे में सरकार की नीति व कार्ययोजना लाभ कमाने वाली व्यावसायिक कम व कल्याणकारी ज्यादा हो तो यह उचित होगा। जनता की तंगी, दुख-तकलीफ की अगर सरकार चिन्ता नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? इसके साथ ही, उन्होंने यूपी सरकार द्वारा करीब 300 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के लगभग 14,500 स्कूलों को स्मार्ट

स्कूल बनाने की घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि यह अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को कथित स्मार्ट पढ़ाई से पहले उन्हें बुनियादी शिक्षा आदि की जरूरतें अर्थात स्कूली बच्चों के सिर पर छत, उनके लिये बेंच, कुर्सी, किताब, शौचालय, मैदान, साफ-सफाई आदि की सही व्यवस्था पूरी की जानी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि यह सब प्रति स्कूल करीब दो लाख रुपये में क्या संभव हो पायेगा, इस पर भी सरकार को सहानुभूतिपूर्वक जरूर विचार करना चाहिए।

कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता केजीपी-12 ने चार शावकों को दिया जन्म

-प्रोजेक्ट चीता को मिली बड़ी सफलता

श्योपुर , एजेंसी।
भारत के कूनो नेशनल पार्क में जन्मी मादा चीता केजीपी 12 ने चार नए शावकों को जन्म दिया है, जो प्रोजेक्ट चीता के लिए बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह घटना इस महत्वाकांक्षी पहल के चार साल पूरे होने के ठीक एक दिन बाद सामने आई है, और भारत में चीता संरक्षण के प्रयासों को नई ऊर्जा प्रदान करती है।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रोजेक्ट चीता के लिए एक ऐतिहासिक और खुशी का पल बताया। उन्होंने कहा, चार साल, चार नई जिंदगियां; उम्मीद, हिम्मत और भारत में चीता संरक्षण की बढ़ती सफलता का एक सुंदर प्रतीक हैं। केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को बधाई भी दी।
इन नए शावकों के जन्म के साथ, भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 52 हो गई है, जिसमें से अब 32 चीते देश में ही पैदा हुए हैं। चीता पुनर्वास कार्यक्रम की हालिया चार वर्षीय समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में 49 चीते कूनो नेशनल पार्क में और तीन गांधी सागर अभयारण्य में मौजूद हैं। यह संख्या नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और हाल ही में बोत्सवाना से लाए गए चीतों तथा उनके भारतीय-जन्मे शावकों को मिलाकर है।
रिपोर्ट के अनुसार, 17 सितंबर, 2022 को लाए गए आठ नामीबियाई चीतों में से तीन और उनके 22 बच्चे जीवित हैं, जबकि 18 फरवरी, 2023 को लाए 12 दक्षिण अफ्रीकी चीतों में से आठ और उनके 10 बच्चे जीवित हैं। इसके अतिरिक्त, 28 फरवरी, 2026 को बोत्सवाना से नौ चीते लाए गए थे। कूनो नेशनल पार्क ने कार्यक्रम की प्रगति पर जोर देकर कहा, चार साल बाद, प्रजनन करने वाली मादाओं का स्थापित होना और दूसरी पीढ़ी के शावकों का जीवित रहना भारत के चीता पुनर्वास कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मजबूती का चरण है।

गठबंधन में दरार? ममता और डीएमके से अलग तीसरा मोर्चा बनाएंगे?

कांग्रेस को हटाने के मूड में ममता बनर्जी?

नई दिल्ली,, एजेंसी।
2029 के लोकसभा चुनाव से पहले भारत की राजनीति में बड़ी हलचल होने के आसार दिख रहे हैं। इसके संकेत हाल ही में हुईं कुछ बैठकों से मिल रहे हैं, जहां द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम (डीएमके) की सांसद कनिमोई ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है। खबरें हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगैर कांग्रेस के एक क्षेत्रीय दलों का गठबंधन तैयार करने की योजना बनाई जा रही है, हालांकि इसे लेकर औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। कनिमोई और ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में मुलाकात की। कालीघाट स्थित पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर हुई इस बैठक में किन मुद्दों पर बात की गई, इसे लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। इससे पहले, डीएमके नेता ने शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले से भी मुलाकात की थी। कहा जा रहा है कि वह जल्द ही आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल से भी मिल सकती हैं।
इन मुलाकातों को एक तीसरे मोर्चे की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। डीएमके के एक नेता ने कहा है कि, हम बगैर कांग्रेस के एक तीसरे मोर्चे की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इधर, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के एक सांसद ने बातचीत में बताया कि, ममता बनर्जी के डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। वह गैर-एनडीए पार्टियों के साथ भी अच्छे रिश्ते बनाए रखती हैं और इंडिया ब्लॉक के उन सदस्यों के करीब हैं जो कांग्रेस समर्थक नहीं हैं। आज की बातचीत सिर्फ उनके और कनिमोई के बीच हुई। इसके अलावा कुछ भी कहना सिर्फ अटकलें लगाना होगा। यह सवाल उठ रहा है कि क्या डीएमके की तरह ममता बनर्जी भी कांग्रेस से नाराज हैं। तमिलनाडु की राजनीति में लंबे समय तक कांग्रेस और डीएमके एक साथ रहे और विधानसभा व लोकसभा चुनाव साथ लड़े, लेकिन 2026 चुनाव के बाद स्थिति बदल गई। कांग्रेस राज्य के सबसे बड़े दल तमिलागा वेत्री कझगम से जा मिली और पुराने साथी डीएमके को छोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि डीएमके ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और इंडिया गठबंधन से भी दूरी बना ली। वहीं, ममता बनर्जी की नाराजगी की एक वजह सीट शेयरिंग हो सकती है। खबरें थीं कि पश्चिम बंगाल की दो सीटों पर

होने वाले आगामी उपचुनाव को लेकर ममता ने कांग्रेस से मदद मांगी थी, जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया। हालांकि, टीएमसी नेता इससे इनकार कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस खुलकर इसे स्वीकार कर रही है। खबरें थीं कि पूर्व मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से रेजीनगर सीट पर समर्थन मांगा था और नंदीग्राम सीट छोड़ने की पेशकश की थी।